जनहितैषी

हिन्दी दैनिक

जनहितैषी अब janhitaishinews.com पर भी

R.N.I. No. 64278/96 वर्ष:29 अंक:132 दिनांक:15-09-2024 रविवार मूल्य : 1 रूपया 50 पैसा पृष्ठ:4 वडोदरा M

हिमाचल प्रदेश में मस्जिदों को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। शिमला के बाद अब मंडी कांगड़ा पालमपुर शिमला के सुन्नी बिलासपुर के घुमारवीं मंडी के जोगेंद्रनगर और कुल्लू के अखाड़ा बाजार में मस्जिदों के बाहर प्रदर्शन हुए हैं।

हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा से सत्य की वकालत करते थे, आजादी के कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर गांधी जी के आदर्शों का असर रहा,

ओडिशा समेत 11 राज्यों में कल भारी बारिश को लेकर रेड व ऑरेंज अलर्ट; हिमाचल में 156 सड़कों पर मलबे

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों और उससे सटे बांग्लादेश के इलाकों के ऊपर गहरा दबाव का क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के अलग-अलग स्थानों पर शनिवार को बहुत भारी बारिश हुई है।

दक्षिण पश्चिम मानसून के आखिरी चरण में हिमालयी राज्यों से लेकर पूर्वी तटीय प्रदेशों में जमकर बारिश हो रही है। मूसलाधार बारिश के चलते विशेष रूप से पश्चिमी हिमालयी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड को भारी संकटों का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह भूस्खलन होने से राष्ट्रीय राजमार्ग समेत 150 से अधिक सड़कों पर यातायात ठप हो गया है। ऊंची चोटियों पर बर्फबारी से मौसम में आई ठंड के बीच लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने रविवार को 11 राज्यों में भारी से बहुत अधिक बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। इनमें ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, पश्चिम बंगाल के गंगा किनारे वाले क्षेत्रों और उससे सटे बांग्लादेश के इलाकों के ऊपर गहरा दबाव का क्षेत्र बना है। इसके पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके प्रभाव से पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड के अलग-अलग स्थानों पर शनिवार को बहुत भारी बारिश हुई है। उत्तरी ओडिशा के मयूरभंज जिले में सबसे अधिक 136 मिमी वर्षा दर्ज की गई है। रविवार को भी झारखंड, छत्तीसगढ़ और 16 सितंबर को पूर्वी मध्य प्रदेश में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है।

चीन सीमा पर पिथौरागढ़ से मिलम से गढ़वाल के मलारी तक गश्त करने के लिए आईटीबीपी के सैनिकों का दल बृहस्पतिवार को मुनस्यारी से रवाना हुआ था। दल में शामिल बिहार निवासी जवान अनिल राम और वल्थी मुनस्यारी निवासी पोर्टर देवेंद्र सिंह लापता हो गए थे।

उत्तरकाशी में उच्च हिमालयी क्षेत्र में भारी बर्फबारी से वुडनकॉल पास पर जा रहे महाराष्ट्र और बंगलुरू के 20 सदस्यीय पर्वतारोहियों के दल को समुद्रतल से 15,419 फीट की ऊंचाई पर स्थित सूकाताल से गंगोत्री लौटना पड़ा। वुडनकॉल पास और उसके बेस कैंप के आसपास भारी बर्फबारी से एवलांच आने के कारण दल ने लौटने का निर्णय लिया। दल देर शाम तक सकुशल गंगोत्री धाम पहुंच गया था। दल को वुडनकॉल पास पार कर खतलिंग ग्लेशियर के बाद मयाली केदारनाथ निकलना था।

हिमाचल प्रदेश में बदले मौसम के बीच लाहौल-किन्नौर की चोटियां बर्फ से सफेद हो गई हैं। चंडीगढ़-मनाली एनएच नौ घंटे बंद रहा। मंडी में नौ मील के पास मलबे की चपेट में एक थार आ गई। पिता और पुत्र ने भागकर जान बचाई। मंडी-पंडोह मार्ग पर वाहनों की लाइनें लगी रहीं। सुबह 8.30 बजे हाईवे बहाल हुआ। किन्नौर के मलिंग में 18 घंटे और निगुलसरी में 14 घंटे बाद एनएच बहाल हो सका। राज्य में 156 सड़कों पर मलबा आने से यातायात बंद है।

अटॉर्नी जनरल ने सीजेआई से कहा.....कुछ संवेदनशील प्रकृति के इसलिए केंद्र रोक रहा

नई दिल्ली (ईएमएस)। भारत सरकार के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि केंद्र के पास मौजूद सेंसिटिव मटेरियल हाई कोर्ट के चीफ जस्टिसों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम की सिफारिशों में बाधा डाल रही है। उन्होंने कोर्ट से पूछा कि संवैधानिक न्यायालयों में नियुक्तियों के मामले में एकमात्र अधिकार रखने वाले कॉलेजियम द्वारा लिए गए निर्णयों के क्रियान्वयन में क्या बाधा आ रही है।

अटॉर्नी जनरल ने कहा कि उन्हें केंद्र से कुछ इनपुट मिले हैं और इनमें से कुछ संवेदनशील प्रकृति के हैं, इसकारण भारत सरकार हलफनामा दाखिल करने से रोक रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन मुद्दों को सार्वजनिक डोमेन में रखना न संस्थान के हित में होगा और न ही इसमें शामिल व्यक्तियों के हित में। वेंकटरमणी ने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि मैं इनपुट और अपने सुझावों को न्यायाधीशों के अवलोकन के खातिर सीलबंद लिफाफे में रखना चाहूंगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कानूनी अधिकारी से अनुरोध किया कि वे सात हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए करीब दो माह पुरानी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के क्रियान्वयन में बाधा डालने वाले मुद्दों को समाधान करें। पीठ एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें केंद्र सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को लागू करने में अड़चन डालने के बजाय तेजी से लागू करना अनिवार्य बनाने की मांग की गई थी।

11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम में सीजेआई चंद्रचूड़ और जस्टिस संजीव खन्ना और बी आर गवई शामिल थे। उन्होंने केंद्र से जस्टिस मनमोहन को दिल्ली हाईकोर्ट का सीजे, राजीव शकधर को हिमाचल प्रदेश का सीजे,सुरेशकुमार कैथ को जम्मू-कश्मीर औरलद्दाख का सीजे, जी एस संधावालिया को मध्य प्रदेश का सीजे, एन एम जामदार को केरल का सीजे, ताशी रबस्तान को मेघालय का सीजे और के आर श्रीराम को मद्रास हाईकोर्ट का सीजे नियुक्त करने की सिफारिश की थी।

हाईकोर्ट जजों की नियुक्तियों और तबादलों के लिए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की कई अन्य सिफारिशें हैं, जो केंद्र सरकार के पास लंबित हैं। सुनवाई के दौरान सीजेआई ने खुलासा किया कि उन्होंने अटॉर्नी जनरल से बात की थी और उनसे कॉलेजियम के प्रस्तावों के कार्यान्वयन में आड़े आ रहे मुद्दों को सुलझाने का अनुरोध किया है। पीठ ने अटॉर्नी जनरल के जवाब का इंतजार करने के लिए सुनवाई अगले सप्ताह के लिए टाल दी।

कुरुक्षेत्र रैली में बोले पीएम नरेंद्र मोदी- कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप

कुरुक्षेत्र(ईएमएस)। हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि गांधी जी हमेशा से सत्य की वकालत करते थे, आजादी के कुछ वर्षों तक कांग्रेस पर गांधी जी के आदर्शों का असर रहा, लेकिन आज की कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप बन गई है। कांग्रेस को झूठ बोलने पर अब शर्म नहीं आती।

कांग्रेस हर रोज एक नया झूठ बोलती है। कांग्रेस देश की एकता पर लगातार हमला कर रही है। कांग्रेस देश पर नक्सलवाद थोप रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही (गांधी) परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है। मगर, जब तक मोदी है, आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहां कांग्रेस की सरकार आई तो इसकी हालत भी हिमाचल जैसी हो जाएगी। जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं हैं। यहां तक कि सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है।

किसानों के मुद्दे पर पीएम ने कहा कि कांग्रेस देश को गुमराह कर रही है। उन्होंने कांग्रेस को चैलेंज दिया कि वे कर्नाटक और तेलंगाना में इन स्कीमों को लागू करें। मोदी ने कहा कि तेलंगाना में कुछ ही महीनों में 1200 किसान खुदकुशी कर चुके हैं। कांग्रेस के लोगों को डूब मरना चाहिए। उनके मुंह में किसानों की मौत का पाप है। हरियाणा में भाजपा सरकार 24 फसलों पर एमएसपी दे रही है।

कांग्रेस एक परिवार को आगे बढ़ाकर राजनीति कर रही

नरेंद्र मोदी ने कहा- कांग्रेस का दलित विरोधी चेहरा हरियाणा से बेहतर कौन जानता है। हरियाणा में जब-जब कांग्रेस की सरकार आती है तो दलितियों का जीना मुश्किल हो जाता है। 2005 में गोहाना में कितना बड़ा कांड हुआ, मिर्चपुर कांड हुआ। 2012 में जो हुआ, उसे याद करके रूह कांप जाती है। तब मैंने यह कहा था कि दिल्ली के शाही परिवार और पूर्व सीएम हुड्डा के मुंह पर ताले गए थे। मैं एक और बात बताऊंगा, कांग्रेस में एक अंदरूनी महाभारत चल रही है। जिस तरह यहां एक परिवार को आगे बढ़ाकर कांग्रेस राजनीति कर रही है, वह पूरा दलित समाज देख रहा है। भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी से लोगों के विकास में जुटी हुई है। जब यहां कांग्रेस की सरकार थी, तबखर्ची और पर्ची के बिना नौकरी नहीं मिलती थी। भाजपा ने इस खेल को खत्म कर दिया है। इसकी प्रशंसा पूरे देश में हो रही है। भाजपा की सरकार ने पूरी ईमानदारी से डेढ़ लाख नौकरियां दीं। हमारे मुख्यमंत्री 25 हजार और नौकरियां देने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के भर्ती रोकों गैंग ने अड़ंगा लगा दिया। हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार आने का मतलब है कि सबका साथ सबका विकास।

कांग्रेस ने वन रैंक वन पेंशन को लटकाया

नरेंद्र मोदी ने कहा कि वीर जवानों के साथ भी कांग्रेस ने धोखा किया है। बीजेपी ने वन पेंशन वन स्कीम लागू की। इससे हरियाणा के डेढ़ लाख हरियाणा के फौजियों को करोड़ों रुपए का फायदा मिला। कांग्रेस ने इसे दशकों से लटकाए रखा था। हमने तीसरी टर्म में भी इसे रिवाइज कर दिया। अक्टूबर से फौजियों को इसका लाभ मिलने लग जाएगा। यहां आने से पहले मैं जम्मू कश्मीर में था। वहां कांग्रेस पार्टी 370 कोफिरसे बहाल करने का संकल्प ले रहीहै।आपको क्या ये मंजूर है। ऐसा पाप करनेवालीकांग्रेस को सजा मिलनी चाहिए। कुछ साल पहले तक वहां हरियाणा के वीर सैनिकों पर जो पत्थर चलते थे, आतंकवादी गोलियां चलाते रहते थे। मेरे हरियाणा के वीर सपूत हर सप्ताह तिरंगे में लिपटकर वापस आते थे। कांग्रेस धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करके उस दौर को वापस लाना चाहती है।

बारामुला में मुठभेड़, तीन आतंकी ढेर

श्रीनगर/बारामुला जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के बीच उत्तरी कश्मीर के बारामुला जिले में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है। 12 घंटे से अधिक चली मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने तीन आतंकियों को मार गिराया है। इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार देर रात पट्टन के चक तापर क्रीरी में आतंकियों की मौजूदगी की सूचना मिली। सुरक्षाबलों तुरंत इलाके की घेराबंदी कर तलाशी अभियान चलाया। सेना का दल जैसे ही आगे बढ़ा तो घिरते देख एक खस्ताहाल में स्कूल इमारत में छिपकर बैठे आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग शुरू कर दी। सतर्क जवानों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई।

अधिकारी के अनुसार अंधेरे का फायदा उठाकर आतंकी फरार न हों, फ्लड लाइट का प्रबंध कर मल्टी टियर सुरक्षा घेरा स्थापित कर दिया गया। शनिवार तड़के फिर से ऑपरेशन शुरू कर तीन आतंकियों को ढेर कर दिया गया। मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को ढेर करने के लिए 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाना पड़ा। मारे गए आतंकियों से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। पुलिस अधिकारी के अनुसार आतंकियों को ढेर करने के लिए 12 घंटे से अधिक समय तक ऑपरेशन चलाना पड़ा।

सूत्रों के अनुसार मारे गए आतंकी टीआरएफ संगठन से जुड़े थे। इनकी शिनाख्त शोपियां के जुनैद रशीद और गांदरबल के बिलाल व माहिर के रूप में हुई है। हालांकि, इसकी अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

ममता बनर्जी और डॉक्टरों की बैठक विफल

कोलकाता: कोलकाता के आरजी कर अस्पताल के मामले में सीबीआई ने संदीप घोष और एक पुलिसकर्मी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले इसी कॉलेज-अस्पताल के भीतर दुष्कर्म-हत्या मामले में इंसाफ की मांग कर रहे प्रदर्शनकारी डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच बैठक विफल रही।

कोलकाता के आरजी कर कॉलेज-अस्पताल के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (ॅंब्) ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और ताला थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल को गिरफ्तार किया है। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक दोनों की गिरफ्तारी वित्तीय अनियमितता मामले में हुई है। उधर, सीएम आवास पर पहुंचे डॉक्टरों के प्रतिनिधिमंडल और मुख्यमंत्री की बैठक विफल रही। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी जैसे आला अधिकारी भी मौजूद रहे। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष और एक पुलिसकर्मी को प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले में गिरफ्तार किया है। सूत्रों ने यह जानकारी दी।

कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की गिरफ्तारी पर एक जूनियर डॉक्टर ने कहा कि वे दोनों की गिरफ्तारी से बहुत खुश हैं। इन दोनों पर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप था। डॉक्टर ने कहा, हम पूर्व प्राचार्य घोष और अभिमंडल की गिरफ्तारी की मांग इसलिए कर रहे थे, क्योंकि इनका नाम सबूतों से छेड़छाड़ करने के मामले में शामिल था। अब जब सीबीआई ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया है, तो हम बहुतखुशहैं। हमारी मांग है कि सीबीआई अन्य सभी आरोपियों को भी गिरफ्तार करे, जिन्होंने सबूतों से छेड़छाड़ की है। मामले में शामिल अन्य लोगों को भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए।

आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में जूनियर डॉक्टर की दुष्कर्म व हत्या के मामले में गतिरोध करने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों के बीच शनिवार को फिर बात नहीं हो सकी। ममता के बुलावे पर बातचीत के लिए उनके घर पहुंचे डॉक्टरों ने बैठक की लाइव स्ट्रीमिंग या वीडियो रिकॉर्डिंग की मांग की। सीएम ने इसे ठुकरा दिया और खुद वीडियो रिकॉर्डिंग कर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें उसकी एक प्रति सौंपने की बात कही।

डॉक्टरों ने कहा कि सीएम के प्रस्ताव पर उन्होंने विचार करने के बाद बैठक में शामिल होने का फैसला किया। जब हमने यह बात स्वास्थ्य राज्यमंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य को बताई, तो हमें कार्यक्रम स्थल छोड़ने के लिए कहा गया क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और वे तीन घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे। डॉक्टरों ने कहा कि हमसे बहुत मनमाने तरीके से जाने को कहा गया। मीडिया के कैमरे के सामने रोते हुए एक अन्य डॉक्टर ने कहा कि इस घटना से राज्य सरकार का असली इरादा सामने आ गया है। यह दिखाता है कि बातचीत को लेकर कौन गंभीर नहीं है। जूनियर डॉक्टरों ने एक वीडियो साझा किया है जिसमें भट्टाचार्य कहती हैं, आज तो सब खत्म हो गया, हम तीन घंटे से इंतजार कर रहे हैं लेकिन आप लोग अंदर नहीं आए।

ऑफिस घर जाते वक्त हुआ हादसा: जलभराव में डूबी कार, दो की मौत

फरीदाबाद(ईएमएस)। गुरुग्राम ग्रेटर फरीदाबाद अपने घर लौट रहे दो युवको की कार गहरे पानी में चली गई। कार के डूबने से दोनों युवकों की वहीं पर मौत हो गई।

मृतकों की पहचान प्रेमाश्रय शर्मा और विराज के रूप में हुई है। दोनों यहां ग्रेटर फरीदाबाद में रहते थे और गुरुग्राम स्थित एचडीएफसी बैंक में जॉब करते थे। देर रात दोनों गुरुग्राम से ग्रेटर फरीदाबाद अपने घर की ओर आ रहे थे। दिन भर हुई वर्षा की वजह से ओल्ड रेलवे अंडरपास में काफी पानी भरा हुआ था। एहतियात के तौर पर पुलिस ने पास में ही एक राइडर खड़ी की हुई थी जो वाहन चालकों को अंदर जाने से मना कर रही थी। देर रात एक एक्सयूवी 700 कर आई और तेजी से अंडरपास की ओर बढ़ गई पुलिस का दावा है कि कार को अंदर जाने से मना किया था लेकिन सवार नहीं माने। इसके बाद कार के अंदर पानी भर गया और वह डूबने लगे। तभी आसपास के लोग आए और पानी के अंदर उतरकर पहुंचे। दोनों युवकों को बाहर निकाला गया।

भारत ने ब्रिक्स में शामिल देशों से कहा- संस्कृति आर्थिक विकास और सामाजिक समावेशन में तेजी लाने की कुंजी

नई दिल्ली (ईएमएस)। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ब्रिक्स में शामिल देशों के संस्कृति मंत्रियों की 9वीं बैठक में भारत के संस्कृति मंत्रालय में सचिव अरुणीश चावला ने वैश्विक विकास रणनीतियों के केंद्र में संस्कृति को रखने की आवश्यकता पर जोर दिया, ताकि इसे सशक्तिकरण, समावेशन और आपसी समझ के लिए एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया जा सके।

सचिव चावला ने सतत विकास और वैश्विक सहयोग के लिए संस्कृति की शक्ति का उपयोग करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता दोहराई। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सांस्कृतिक रचनात्मकता, वाणिज्य और सहयोग के बीच तालमेल के दृष्टिकोण के अनुरूप है ताकि एक समान, टिकाऊ और समावेशी दुनिया का निर्माण किया जा सके। वर्ष 2023 में भारत की अध्यक्षता के दौरान जी20 में भारत के रुख को जारी रखते हुए, भारत ने 2030 के बाद के वैश्विक विकास एजेंडे में संस्कृति को एक स्वतंत्र लक्ष्य के रूप में मान्यता देने की वकालत की, जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक समावेश और सतत विकास को आगे बढ़ाने में इसकी परिवर्तनकारी क्षमता पर प्रकाश डाला गया। यह भारत के अपने सांस्कृतिक पुनर्जागरण प्रयासों के अनुरूप है, जिसका उद्देश्य नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देते हुए अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखना और बढ़ावा देना है।

सेना की इंफ्रेंट्री यूनिट को मिली स्वदेशी एंटी ड्रोन गन, स्वदेशी स्टार्टअप ने तैयार किया

नई दिल्ली (ईएमएस)। ड्रोन के बढ़ते खतरे के बीच भारतीय सेना की इंफ्रेंट्री यूनिट को स्वदेशी एंटी ड्रोन गन मिली है। इतना ही नहीं जल्द ही सेना को इससे ज्यादा रेंज वाली एंटी ड्रोन गन भी मिलेगी। इस एंटी ड्रोन गन को स्वदेशी स्टार्टअप ने तैयार किया है। करीब चार माह पहले ही सेना की एक यूनिट को ये गन सप्लाई की गई हैं। इससे कुछ बड़े एंटी ड्रोन सिस्टम को भी बनाया गया है और आर्मी और एयरफोर्स से समझौता साइन हुआ है। इसकी डिलीवरी नवंबर में शुरू होगी।

पूरी दुनिया में आजकल ड्रोन और एंटी ड्रोन की बात कर रही है, फिर रूस और यूक्रेन का युद्ध हो या इस्राइल और हमास के बीच की जंग। ड्रोन का इस्तेमाल जमकर हो रहा है। दुनिया भर की फौज ड्रोन के इस्तेमाल को लेकरसतर्क हैं। भारत में भी लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम पर काम हो रहा है और कई स्टार्टअप इस पर काम कर रहेहैं।इसीकड़ीमें बिग बैंग बूम सॉल्यूशंस ने सेना को एंटी ड्रोन गन सप्लाई की हैं। स्टार्ट अप के वाइस प्रेजिडेंट गौरव शर्मा ने बताया कि एंटी ड्रोन गन और डिटेक्टर की जोड़ी है। डिटेक्टर 360 डिग्री में चार किलोमीटर के दायर में किसी भी ड्रोन को डिटेक्ट कर सकता है। इस एक टैबलेट से जोड़ा जाता है और अगर इसके दायरे में कोई भी ड्रोन आता है तब इसमें अलार्म बजेगा।

डिटेक्टर के द्वारा ड्रोन की डायरेक्शन का पता चलते ही उस डायरेक्शन में एंटी ड्रोन गन को करना होता है और इसके बटन को दबाना होता है। गन से 45 डिग्री की एक बीम निकलती है जो आगे जाकर एक जाल की तरह ड्रोन को घेर लेती है और ड्रोन ब्लाइंड हो जाता है। ड्रोन के पास कोई सिग्नल नहीं रहता है, वह जाम हो जाता है। इसमें अलग-अलग तरह के ड्रोन को काउंटर करने के लिए अलग अलग तरह की फ्रिक्वेंसी है। यह गन बैटरी से चलती है, इस मोबाइल की तरह ही चार्ज किया जा सकता है। पूरी चार्ज बैटरी 8 घंटे काम करती हैपैदल सैनिकों के हिसाब से बनाया गया है, ताकि पैदल सैनिक इस फॉरवर्ड पोस्ट तक ले जा सकें। कई जगह सेना की पोस्ट 15 हजार से लेकर 18 हजार फीट तक की ऊंचाई पर हैं। गन का वजन 4 किलो है और डिटेक्टर का वजन करीब 9 किलो है। गन की रेंज 2 किलोमीटर है।

आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की जरूरतें स्वदेशी कंपनियां पूरी कर सकें इसलिए रक्षा मंत्रालय आईडीईएक्स प्रोग्राम के तहत स्टार्टअप को प्रोटोटाइप बनाने के लिए फंड देता है। सेनाओं की जरूरत के हिसाब से अगर स्टार्टअप ने कुछ डिवेलप किया है, तब प्रोटोटाइप के लिए मंत्रालय मदद करता है और फिर उस प्रॉडक्ट को सेनाओं के लिए लिया जाता है। इस वक्त पूरी दुनिया में ड्रोन का खतरा बढ़ा है और एंटी ड्रोन सिस्टम पर लगातार काम हो रहा है। सेना ने भी बॉर्डर एरिया में एंटी ड्रोन सिस्टम बढ़ाए हैं।

उत्तराखंड में भारी बारिश से कई जगह भूस्खलन, हाईवे अवरुद्ध, कई यात्री फंसे

चमोली,(ईएमएस)। भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे लामबगड़, नंदप्रयाग, सोनाला और बैराज कुंज में सड़क अवरुद्ध हो गई। भूस्खलन के कारण सकोट और नंदप्रयाग के बीच वैकल्पिक मार्ग भी अवरुद्ध हो गया है।

चमोली पुलिस ने कहा कि जिले में भारी बारिश के कारण बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके कारण सड़क अवरुद्ध हो गई। सुरक्षा की दृष्टि से चमोली पुलिस ने यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रोक रखा है। इससे पहले पुलिस ने सोशल मीडिया पर कहा था कि बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कमेड़ा (गौचर), नंदप्रयाग (चमोली) और छिनका (चमोली) में अवरुद्ध है। बाद में उन्होंने बताया कि छिनका में अवरुद्ध सड़क को यातायात के लिए खोल दिया गया है। चमोली पुलिस ने यह भी बताया कि जिले में कमेड़ा के पास अवरुद्ध बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है।

सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण एसडीआरएफ की टीमों और जिलाधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने का निर्देश दिया है। उन्होंने लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने की भी सलाह दी थी। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के कई दक्षिणी जिलों के लिए रेड अलर्ट और अन्य भागों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उत्तर-पश्चिम यूपी पर बना दबाव 12 घंटों के अंदर कम दबाव वाले क्षेत्र में कमजोर पड़ने की उम्मीद है। बरेली के पास केंद्रित मौसम प्रणाली दक्षिणी उत्तराखंड और यूपी के कुछ हिस्सों में बिखरे बादल और तीव्र संवहन का कारण बनेगी। उत्तरी उत्तराखंड, पूर्वी राजस्थान और उत्तर-पश्चिम मध्य प्रदेश में भी बारिश और तेज़ हवाएं चलने का अनुमान है।

पीएम मोदी का राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान पर तंज बदसलूकी और मारपीट करते

बीजेपी के मीडिया सेल प्रमुख ने उठाए कांग्रेस समर्थित पत्रकारों पर सवाल

डोडा (ईएमएस)। अमेरिका में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के कार्यक्रम के दौरानपत्रकारसेबदसलूकीका मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदीकीतरफ से भी इस लेकर प्रतिक्रिया सामने आ गई है। पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर के डोडा में रैली दौरान अमेरिका में पत्रकार के साथ बदसलूकी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस परनिशाना साधा है। इसके साथ हीउन्होंनेभारत के बेटे का अमेरिका में अपमान बताया है। पीएम मोदीनेअमेरिकामें पत्रकार के साथ हुई बदसलूकी पर सवाल उठाते हुए राहुल गांधी के मोहब्बत की दुकान के दावे पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि वे मोहब्बत की दुकान चलाने का दावा करते हैं। लेकिन हमारे देश के एक पत्रकार पर अमेरिका में कांग्रेस द्वारा बदसलूकी की गई।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत के एक सपूत का अमेरिका में अपमान हुआ है। पीएम मोदी ने कहा कि ये लोग अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के चैंपियन होने का दावा करते हैं, वे क्रूरता में शामिल थे।दरअसल, एक भारतीय मीडिया हाऊस के वाशिंगटन स्थित संवाददाता ने हैरतअंगेज खुलासा करते हुए जानकारी दी कि टेक्सास के डलास में राहुल गांधी की टीम द्वारा उन पर कैसे अटैक किया गया। पत्रकार ने दावा किया कि राहुल गांधी के सहयोगियों ने उनका फोन तक छीन लिया और बांग्लादेशी हिंदुओं पर हमलों के बारे में पूछे गए सवाल के फुटेज को जबरन डीलिट करने के लिए मजबूर किया।

बीजेपी के मीडिया सेल प्रमुख अमित मालवीय ने पूरी घटना का ब्यौरा अपने एक्स अकाउंट पर शेयर करते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय मीडिया हाऊस एक बड़ा मुद्दा बनाता हैं और अपने पत्रकार पर हमले को उजागर करने के लिए अपने मंच का उपयोग करते हैं। यह देखना भी उतना ही दिलचस्प होगा कि राजदीप सरदेसाई जैसे कांग्रेस के धुरंधर इस घटना को प्राइम टाइम पर लेते हैं या नहीं। बेरोजगार कांग्रेस की ओर झुकाव रखने वाले यूटयूब पत्रकारों की चुप्पी स्पष्ट है। लेकिन क्या प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और अन्य मीडिया व्यस्त निकाय एक साथी पत्रकार पर आक्रामकता के इस कृत्य के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस की निंदा करेंगे?

निर्यात बढाने से किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाएंगे

- इस निर्णय से भारत के सोयाबीन किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसानों को उनकी फसल का उचित दाम दिलाने के लिए निर्यात को बढ़ा रही है, ताकि किसान अपनी फसल का अधिक से अधिक दाम प्राप्त कर पाएं।

अमित शाह ने ''X'' प्लेटफॉर्म पर अपने एक पोस्ट में कहा कि किसान हित सर्वोपरि रखते हुए मोदी सरकार ने तीन महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं –

1) मोदी सरकार ने प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (ईंड्ढ) हटाने और निर्यात शुल्क को 40ञ्ज से 20ञ्ज करने का निर्णय लिया है। इससे प्याज का निर्यात बढ़ेगा, जिससे प्याज उत्पादक किसानों की आय में वृद्धि होगी।

2) सरकार ने बासमती चावल पर भी ईंड्ढ समाप्त करने का निर्णय लिया है, जिससे बासमती चावल के उत्पादक किसान इनका निर्यात करके अधिक मुनाफा प्राप्त कर पाएंगे।

3) साथ ही, मोदी सरकार ने कच्चे पाम, सोया और सूरजमुखी तेलों के आयात में डयूटी को 12.5ञ्ज से 32.5ञ्ज बढ़ाने व इनके रिफाइंड तेलों पर डयूटी को 13.75ञ्ज से 35.75ञ्ज करने का निर्णय लिया है। इससे भारत के सोयाबीन के किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और उनकी आय बढ़ेगी।

इस बार का चुनाव तीन खानदानों और नौजवानों के बीच -पीएम मोदी

डोडा(ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू-कश्मीर के डोडा में एक बड़ी चुनावी रैली कर रहे हैं। 42 साल में ऐसा पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री डोडा में जनसभा कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष को निशाने पर लेते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में आ रहा बदलाव हमारी सरकार की बीते 10 सालों की कोशिशों का नतीजा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद आज अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि खूबसूरत जम्मू-कश्मीर को परिवारवाद ने खोखला कर दिया, राजनीतिक दलों को सिर्फ बच्चों की चिंता रही है। उन्होंने कहा कि इस बार का चुनाव तीन खानदानों और जम्मू कश्मीर के नौजवानों के बीच है।

भीड़ को देखकर गदगद नजर आए पीएम मोदी ने कहा, आप सब यहां डोडा, किश्तवाड़ और रामबन के अलग-अलग हिस्सों से पहुंचे हैं।यहां आने के लिए आपने घंटो सफर किया है, इसके बावजूद आपके चेहरे पर थकान का नामोनिशान नहीं है और चारों तरफ जोश ही जोश है। आपका ये प्यार, आपके ये आशीर्वाद मैं आपके लिए और देश के लिए दोगुनी, तिगुनी मेहनत करके चुकाऊंगा। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण करेंगे।

प्रधानमंत्री ने कहा कि आजकल ये लोग संविधान को अपनी जेब में रखते हैं। ये दिखावा ये अपने काले कारनामों को छिपाने के लिए कर रहे हैं। हकीकत क्या है, ये जम्मू कश्मीर का बच्चा-बच्चा जानता है। इन लोगों ने बाबा साहेब के बनाए संविधान की आत्मा को नोच दिया था। वरना क्या कारण था कि हमारे जम्मू कश्मीर में दो संविधान चलते थे। क्यों यहां के लोगों

जन हितैषी

सीबीआई अब भाजपा के 'पिंजरे का तोता बना

भारत की शीर्ष जांच एजेंसी, सीबीआई पर समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। सीबीआई की जांच में निष्पक्षता और उसके तौर-तरीके को लेकर शुरुआती दौर पर सीबीआई के ऊपर सभी को बहुत भरोसा था। पिछले 2 दशकों में यह भरोसा पूरी तरह से टूटता हुआ दिख रहा है। सीबीआई की निष्पक्षता पर कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट में आलोचना की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सीबीआई को 'पिंजरे का तोता' कहा था। 2014 से केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने एक बार फिर सीबीआई जैसी महत्वपूर्ण संस्था के ऊपर पिंजरे में बंद तोते के रूप में टिप्पणी की है। यह टिप्पणी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरह से सीबीआई ने पिछले दो वर्षों से अपना शिकंजा कसकर रखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर जैसे ही ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल की जमानत हुई। उसी मामले में 2 साल के बाद सीबीआई ने जेल के अंदर से केजरीवाल की गिरफ्तारी कर ली। सुप्रीम कोर्ट को इस कारण से सीबीआई के ऊपर सबसे सख्त टिप्पणी करनी पड़ी। 2013 में कोयला घोटाले की जांच में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को पिंजरे का तोता कहा था। अब केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने वही टिप्पणी की है। सीबीआई अपने राजनीतिक आकाओं के इशारे पर काम करती है। सीबीआई की कार्य प्रणाली से यह खुलासा, जांच एजेंसी की स्टेटस रिपोर्ट को, सरकार की मंजूरी के बाद किया गया। यह एक गंभीर मुद्दा है, जिसने सीबीआई की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं।

सीबीआई का गठन एक स्वतंत्र जांच एजेंसी के रूप में हुआ था। जिसका उद्देश्य अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रभावी जांच कर कार्रवाई करना था। जैसे-जैसे समय बीतता गया, सीबीआई के अधिकारियों के ऊपर राजनीतिक प्रभाव बढ़ता गया। केंद्र में किसी भी दल की सरकार हो। सीबीआई का उपयोग सरकारें राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने अथवा बचाने के लिए किया जाने लगा। पिछले दो दशकों में पूरी तरह से यह स्पष्ट हो गया है। प्रश्न उठता है, क्या सीबीआई अपनी वैधानिक भूमिका बनाए रखने में स्वतंत्र हैं? या सरकार के इशारे पर काम करने वाली राजनीतिक उपकरण का हिस्सा बन चुकी है? सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी सीबीआई की स्वतंत्रता पर सरकार का शिकंजा है। सरकार के विपक्षियों का उत्पीड़न करने की सीबीआई जांच एजेंसी की भूमिका सामने आई है। लोकतंत्र की शासन व्यवस्था में, जांच एजेंसियों का निष्पक्ष होना, आवश्यक है। सभी जांच एजेंसियां कानून और न्याय के लिए रीढ़ के हड्डी की तरह होती हैं। अगर जांच एजेंसियां राजनीतिक दवाब में काम करेंगी, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था और न्यायिक प्रणाली पर विश्वास करना संभव नहीं होगा। सीबीआई के अधिकारी कहते हैं, वह निष्पक्षता के साथ काम करने की कोशिश करते हैं। कई मामलों में सरकार की स्वीकृति के बिना कार्रवाई करना संभव नहीं होता है। शीर्ष अधिकारियों की नियुक्ति, पोस्टिंग और कार्यकाल केंद्र सरकार ही तय करती है। ऐसी स्थिति में सरकार को इग्नोर करना सीबीआई के वश की बात नहीं है। कुछ इसी तरह की स्थिति चुनाव आयोग की देखने को मिल रही है। केंद्रीय प्रवर्तन निदेशालय की भी लगभग यही स्थिति है। संवैधानिक संस्थाओं की निष्पक्षता और जवाबदेही तय करने के लिए वर्तमान व्यवस्था को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं और जांच एजेंसियों को सरकार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग आयुक्त और सदस्यों की नियुक्ति पर एक फैसला दिया था। जिसमें सीजेआई, प्रधानमंत्री और नेता प्रतिपक्ष की कमेटी को चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करने का अधिकार दिया था। जिसे सरकार ने कानून बनाकर पलट दिया। अब प्रधानमंत्री उनके द्वारा एक नियुक्त मंत्री तथा नेता प्रतिपक्ष चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कर रहे हैं। इसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट चुप है। वर्तमान चुनाव आयोग को लेकर 68 फ़ीसदी जनता में यदि अविश्वास है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे चिंता का विषय है। समय की मांग है, सीबीआई सहित अन्य संवैधानिक संस्थाओं को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं अधिकार संपन्न बनाया जाए। सरकारों के ऊपर उनकी निर्भरता नहीं हो। इसके लिए जरूरी है, संवैधानिक संस्थाओं से राजनीतिक नियंत्रण पूरी तरह से समाप्त किया जाए। संवैधानिक संस्थाओं को न्यायपालिका तथा संसद के प्रति जवाबदेह बनाया जाए। भारतीय संविधान में न्यायपालिका और संसद ही सर्वोच्च संस्थाएं हैं। संवैधानिक संस्थाओं के कामकाज उनके निर्णय, संवैधानिक प्रमुख की नियुक्ति इत्यादि को लेकर जिस तरह के सवाल सरकार पर उठ रहे हैं। न्यायपालिका की जिम्मेदारी है कि वह न्यायपालिका और संसद की सर्वोच्चता जो फिलहाल खत्म होती जा रही है, इसे फिर से बहाल करे। भाजपा के नेता और प्रवक्ता भविष्य में सीबीआई को पिंजरे में बंद तोता नहीं कह पाएंगे। क्योंकि अब यह टैग केंद्र की मोदी सरकार के ऊपर भी चिपक गया है।

बुढ़ापे का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच बनाने की सराहनीय पहल

(लेखक- ललित गर्ग/ ईएमएस)

केंद्र सरकार ने अब सत्तर साल से ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 'आयुष्मान भारत' योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जो सुखद एवं स्वागतयोग्य कदम है। अपने देश के करीब साढ़े चार करोड़ परिवार के छह करोड़ बुजुर्ग इस योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज करा सकेंगे। दरअसल वर्ष 2018 में शुरू हुई आयुष्मान भारत योजना में अब तक केवल गरीब परिवार ही शामिल हो सकते थे, जिन्हें पांच लाख का कैशलेस कवर दिया जाता था। अब इस सार्वभौमिक स्वास्थ्य योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। इस योजना से हम एक ऐसी दुनिया बना सकेंगे जहाँ हर बुजुर्ग अपने बुढ़ापे को गरिमा, आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्वस्थता के साथ जी सकेंगे। इसके लिये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी जनकल्याणकारी सरकार को साधुवाद दिया जाना चाहिए। पारिवारिक एवं सामाजिक घोर उपेक्षा एवं उदासीनता के कारण बुढ़ापा अपने आप में एक रोग ही बनता गया है। जब आय के स्त्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। संयुक्त परिवारों के विघटन और एकल परिवारों के बढ़ते चलन ने इस स्थिति को नियंत्रण से बाहर कर दिया है। उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार की नयी पहल का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन हुआ तो यह फैसला इस आयुवर्ग के बुजुर्गों की सेहत को लेकर सुरक्षा कवच का काम करेगा। यह जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही थी क्योंकि आने वाले बीस वर्ष में भारत की बुजुर्ग आबादी तीन गुना होने की संभावना है।

नये भारत-विकसित भारत की उन्नत एवं आदर्श संरचना बिना वृद्धों की सम्मानजनक स्थिति के संभव नहीं है। यदि परिवार के वृद्ध कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत कर रहे हैं, रुग्णावस्था में बिस्तर पर पड़े कराह रहे हैं, भरण-पोषण एवं उचित स्वास्थ्य-सेवाओं को तरस रहे हैं तो यह हमारे लिए वास्तव में लज्जा एवं शर्म का विषय है। वर्तमान युग की बड़ी विडम्बना एवं विसंगति है कि वृद्ध अपने ही घर की दहलीज पर सहमा-सहमा खड़ा है, वृद्धों की उपेक्षा स्वस्थ एवं सुसंस्कृत परिवार परम्परा पर तो काला दाग है ही, शासन-व्यवस्थाओं के लिये भी लज्जाजनक है। हम सुविधावादी एकांगी एवं संकीर्ण सोच की तंग गलियों में भटक रहे हैं तभी वृद्धों की आंखों में भविष्य को लेकर भय है, असुरक्षा और दहशत है, दिल में अन्तहीन दर्द है। इन त्रासद एवं डरावनी स्थितियों से वृद्धों को मुक्ति दिलाने एवं उनके स्वास्थ्य विषयक खर्चो एवं चिन्ताओं को दूर करने के लिये केन्द्र सरकार ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अन्तर्गत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय लाभ देने का फैसला लिया है, वह सराहनीय एवं प्रासंगिक निर्णय है। इस फैसले की जरूरत इसलिए थी क्योंकि सामाजिक सुरक्षा के मामले में भारत बहुत पीछे है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वे 2019-21 की रिपोर्ट से पता चलता है कि देश में ऐसे परिवारों की संख्या केवल 41 प्रतिशत है, जिनके कम से कम एक सदस्य का स्वास्थ्य बीमा हो। बिहार, महाराष्ट्र जैसे बड़ी आबादी वाले राज्यों में तो यह राष्ट्रीय औसत के करीब आधे के बराबर है। स्वास्थ्य बीमा को लेकर यह उदासीन रवैया हमारी उस आदत की वजह से है, जिसमें ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि जब बीमारी आएगी तो देखा जाएगा। बहुत से लोग जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा को एक ही चीज समझ लेते हैं। लेकिन, जब बीमारी सिर पर आती है, तो पूरे घर के बजट को तहस-नहस एवं असंतुलित कर देती है। सरकार का मौजूदा कदम कई परिवारों को ऐसे आर्थिक दुष्चक्र में फंसने से बचा सकता है। भारत में इलाज दिनों-दिन महंगा होता जा रहा है। जब आय के स्त्रोत सिमट जाते हैं और बच्चों से पर्याप्त मदद नहीं मिलती तो शरीर में रोग दस्तक देने लगते हैं, फिर महंगे इलाज की चिंता और बढ़ जाती है। अकसर भारत में कर्मचारी व आम लोग सोचते हैं कि वे जीवन भर आयकर चुकाते हैं, लेकिन बुढ़ापे में सरकार की ओर से सामाजिक सुरक्षा ना के बराबर होती है। लेकिन अब मोदी सरकार ने लोकतंत्र के सामाजिक कल्याणकारी स्वरूप को तरजीह दी है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं उनकी सरकार अनेक स्वस्थ एवं आदर्श समाज-निर्माण की योजनाओं को आकार देने में जुटी है, उसने वृद्धों को लेकर भी चिन्तन करते हुए वृद्ध-कल्याण योजनाओं को लागू किया है। इन योजनाओं को लागू करने की जरूरत इसलिये सामने आयी है कि वृद्धों को आत्म-गौरव के रूप में स्वीकार करने की अपेक्षा, बंधन माना जाने लगा है। वृद्धों को लेकर जो गंभीर समस्याएं आज पैदा हुई हैं, वह अचानक ही नहीं हुई, बल्कि उपभोक्तावादी संस्कृति तथा महानगरीय अधुनातन बोध के तहत बदलते पारिवारिक-सामाजिक मूल्यों, नई पीढ़ी की सोच में परिवर्तन आने, महंगाई के बढ़ने और व्यक्ति के अपने बच्चों और पत्नी तक सीमित हो जाने की प्रवृत्ति के कारण बड़े-बूढ़ों के लिए अनेक समस्याएं आ खड़ी हुई हैं। अब जब स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ाया गया है तो यह उम्मीद की जानी चाहिए कि खर्च को लेकर परिजनों का डर कम होगा। इस योजना का पूरा खाका सामने आना बाकी है। लेकिन यह सुनिश्चित तो करना ही होगा कि बीमा सुरक्षा कवच होने के बावजूद बुजुर्ग मुफ्त उपचार से वंचित न रह जाएं। खास तौर से सरकारी स्वास्थ्य बीमा योजनाओं को लेकर निजी अस्पतालों के रवैये को देखते हुए यह चिंता ज्यादा जरूरी हो जाती है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के अनुसार भारत में औसत आयु 67.3 साल है। पिछले दो दशकों में ही औसत आयु में पांच बरस से अधिक का इजाफा हो चुका है। निश्चित ही यह अच्छी खबर है, लेकिन इसके साथ यह चिंता भी जुड़ी हुई है कि देश में दिल से जुड़े रोगों और डायबिटीज के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। अन्य रोग भी तेजी से बढ़ रहे हैं। अनुमान लगाया गया है कि भारत में 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की जो आबादी वर्ष 2011 में 8.6 प्रतिशत थी, वह बढ़कर 2050 तक 19.5 फीसदी हो जाएगी। यह भी अनुमान है कि 2030 तक भारत में स्वास्थ्य देखभाल का 45 प्रतिशत खर्च बुजुर्ग मरीजों पर होगा। ऐसे में बुजुर्गों के सामने अनेक अन्य समस्याओं के साथ नई एवं असाध्य बीमारियां और उनका महंगा इलाज बड़ी समस्या है। ऐसी स्थितियों में अब इस योजना का लाभ सभी बुजुर्गों को दिया जाएगा। बहुत संभव है कि इस समय जब कुछ राज्यों में चुनाव की प्रक्रिया चल रही है तो इस घोषणा के राजनीतिक निहितार्थों पर चर्चा हो सकती है। लेकिन भाजपा ने 2024 में लोकसभा चुनाव के लिये जारी घोषणापत्र में किये वायदे को ही आकार दिया है।

वरिष्ठ नागरिक इस योजना का लाभ निजी व राजकीय अस्पतालों में ले सकते हैं। वहीं सरकार की ओर से बताया गया है कि जो सत्तर साल से अधिक के नागरिक प्राइवेट बीमा योजना या फिर राज्य कर्मचारी बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं, वे भी नई योजना का लाभ लेने के अधिकारी होंगे। लेकिन उन्हें इस योजना के लिये आवेदन करना होगा। सरकार ने फिलहाल इस योजना के लिये करीब साढ़े तीन हजार करोड़ का बजट रखा है और आवश्यकता पड़ने पर बजट बढ़ाने की बात कही है। सरकार ने बजट में स्वास्थ्य के लिए कोटा बढ़ाया है। हालांकि चीन और अमेरिका की तुलना में यह अब भी कम है। मेडिकल सुविधाएं एवं साधन बढ़ाने के साथ यह इंतजाम भी करना होगा कि आम जनता उसका फायदा उठा सके। सरकार का हालिया फैसला इसी दिशा में उठाया गया कदम है, लेकिन यह भी सुनिश्चित करना होगा कि योजना को सही ढंग से लागू किया जाए। मुफ्त उपचार से भी बड़ी जरूरत सत्तर साल की उम्र पार वरिष्ठ नागरिकों की नियमित सेहत जांच की है। अस्पतालों की भीड़ में जांच कराना इनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है। ऐसे में बुजुर्गों के घर तक मोबाइल स्वास्थ्य जांच सेवा भी इस योजना में लागू हो तो सोने पर सुहागा हो सकता है। सरकार को भविष्य में वृद्धों के लिये अलग से अस्पताल संचालित करने के बारे में भी सोचना चाहिए।

पैगंबर साहब की नसीहतों ने बदला समाज

(ईद मिलादुन्नबी पर विशेष)

हजरत पैगंबर मोहम्मद साहब की विलादत को पूरी दुनिया में जश्न की तरह मनाया जाता है, इसीलिए इसे ईद-ए-मिलादुन्नबी भी कहा जाता है। मोहम्मद साहब वही नबी थे, जिनके आने के पहले इंसानियत अंधी और अखलाक बहरा था, और इंसान का किरदार मैला हो गया था। पूरे अरब में हिंसा का बोलबाला था। औरतें और बच्चे महफूज नहीं थे। लोगों के जान-माल की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं थी। इस अंधेरे दौर से दुनिया को बाहर निकालने के लिए अल्लाह ने हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम को पैगंबर बनाया। मोहम्मद साहब के बताए आदर्शों, नसीहत और सीख के बाद इंसान, इंसान से मोहब्बत करने लग गया था। जुल्मो-सितम की जगह अदल व इंसाफ ने ले ली थी। तलवार के कब्जे पर रखे हाथ अब तालीमे अखलाक के लिए मैदान में निकल आए थे। यह वही 'मोहम्मद' थे जिन्होंने इंसान को दुनियावी और दीनी तालीम देते हुए हक के रास्ते पर चलने की नसीहत दी। उन्होंने ऐसे आदर्श समाज की स्थापना की जिसमें कई कबीलों और जातियों के लोग बिना किसी भेदभाव के समान अधिकारों के साथ रह सकें। मोहम्मद साहब को अब्द, बशीर, शाहिद, मुबारशीर, नाथिर, सिराज मुनीर, अल मुजम्मिल और अहमद के नाम से भी जाना जाता है। अरब के लोग उन्हें अल-अमीन और अल-सादिक के नाम से भी पुकारते थे। पैगंबर हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहे वसल्लम ने ही इस्लाम धर्म की स्थापना की है। आप हजरत सल्ल. इस्लाम के आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कयामत तक कोई नबी नहीं आने वाला।

इस्लामिक कैलेंडर के मुताबिक 570 ईसवीं में 12 रबीउल अव्वल मोहम्मद की पैदाईश का दिन। अपने पिता अब्दुल्लाह के इस दुनिया से रूखसत हो जाने के बाद जन्मे इस मासूम बच्चे के बारे में किसने सोचा की थी कि यह शराब-ओ शबाब में खोई, बर्बर और भोग-विलास को अपना धर्म समझने वाली कबीलाई अरब सभ्यता की दशा और दिशा बदलने वाला देवदूत होगा। आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब आपकी पैदाइश के दिन ही आपको खाना-ए-काबा ले गए और तवाफ कराकर लाए, और आपका नाम मुहम्मद रखा। आपकी वालिदा ख्वाब में फरिश्ते ने आपका नाम अहमद बताया और इस तरह आपके दो नाम रखे गए। नबी साहब के ये दोनों ही नाम असली है। पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम दुनिया में सबसे लोकप्रिय नामों में से एक है।

आपके पिता की मौत उनके जन्म से पहले ही हो गई थी, इसके बाद कुछ सालों बाद सिर से मां का साया भी उठ गया। 6 साल की उम्र में अनाथ हो गए, वह अपने चाचा अबू तालिब की सरपरस्ती में रहे। तब उनकी माली हालत भी ठीक नहीं थी। तब वे दमस्क में एक ऊंट की देखभाल करने लगे। 12 साल की उम्र में आप अपने चाचा अबू तालिब के साथ अपने पहले व्यावसायिक सफर पर गए और इसके बाद खुद व्यवसाय पर जाने लगे। मोहम्मद साहब अपने खाली वक्त में वह जबल अल-नूर पर्वत पर 'गार-ए-हिरा' में जाकर ईबादत में मशगूल हो जाते थे। उनके पास ना तो कोई दौलत थी और न सरमाया। ना सोने-चाँदी, हीरे-जवाहारात के ढेर। फिक्रो-फाका, गरीबी और तंगहाली को देख कर कर्म विरोधी लोग अक्सर कहते थे कि 'ये कैसा नबी है जो रहता है टूटे हुए हुजरे में, बैठता है खजूर की चटाई पर, पहनता है फटी हुई चादर और दावा करता है सारे कायनात के नबी होने का'। लेकिन ये वही नबी थे जिनके वादे को ईमाम हुसैन ने कर्बला में अपनी शहादत देकर पूरा किया और इंसानियत को ताकयामत के लिए बचा लिया।

मोहम्मद साहब का पूरा जीवन और उनके किए हर काम में कोई न कोई संदेश जरूर छिपा होता था। मसलन, हजरत खदीजा से मोहम्मद साहब की शादी। 25 साल की आयु में आपने 40 साल की विधवा से शादी की। उनके इस फैसले में विधवा विवाह का सामाजिक संदेश छिपा हुआ था। मक्का के बाहर एक पहाड़ पर सन् 610 में ईश्वरी संदेश या वही के जरिए उन्हें नुबुवत मिली अर्थात पैगंबर बनाए जाने का संदेश मिला। उस वक्त 40 साल के थे। हजरत मोहम्मद साहब पर जो अल्लाह की पवित्र किताब उतारी गई है, वह है कुरआन। अल्लाह ने फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अलै. के मार्फत पवित्र संदेश (वही) सुनाया। उस संदेश को ही कुरआन में संजोया गया है। कुरान वह पाक और मुकद्दस किताब है जो आज भी लोगों को भलाई के रास्ते पर चलने का संदेश दे रही है।

मोहम्मद साहब की पैदाईश, अरब की सरजमी पर उस समय हुई है जब इंसानियत कराह रही थी। बाप अपनी बच्ची को उसकी हिफाजत के डर से जिंदा जला देते थे। औरत नुमाइश, भोग एवं विलास की वस्तु थी। नाहक तौर पर अरब कबीले एक-दूसरे से जंग करते थे। जहालत के कारण इंसानियत ही खत्म हो गई थी। ऐसे दौर में मोहम्मद साहब ने लोगों को सहीं रास्ता बताया। औरतों को उनका पूरा हक देने, उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव करने की हिदायत दी। मोहम्मद साहब के कहना था कि बेटी तो किस्मत वालों के यहां पैदा होती है। इसी तरह आपने बेटे-बेटी की बीच भेदभाव को गलत करार दिया। आपने मां-बाप का मर्तबा बताया और बच्चों को मां-बाप की नाफरमानी न करने की नसीहत दी।

न तो ईसा मसीह की तरह मोहम्मद को जन्म से ही अपने नबी होने का अंदाजा था न ही वे मूसा की तरह बेशुमार चमत्कारों के धनी थे। वे जागीर या सल्तनत देकर भी जमीं पर भेजे नहीं गए थे, फिर भी लोगो में मकबूल थे। लोग प्रेम से इन्हें 'सादिक' यानि सच्चा या 'अमीन' यानि अमानतदार कह कर बुलाते थे। मोहम्मद साहब के चेहरे पर नूर था। वह लोगों की जरूरतें पूरी करते, अच्छे कामों के लिए लोगों को प्रेरित करते। आप ने कभी दो वक्त का खाना नहीं खाया, एक वक्त खाना खाते और उसमें भी सिर्फ एक ही सब्जी। वह कभी अकेले नहीं खाते बल्कि दूसरे लोगों को न्यौता देकर बुलाते और उनके साथ खाना खाते। आप गरीब और बीमारों की देखभाल किया करते थे। सही मायनों में आप नेकी, प्रेम, उदारता एवं पवित्रता के प्रतीक थे।

मोहम्मद साहब के जन्म को भी मुसलमान ईद की तरह मनाते हैं इसलिए इसे ईद मिलाद उन-नबी भी कहा जाता है। ईद का अर्थ होता है उत्सव मनाना और मिलाद का अर्थ होता है जन्म होना। मीलाद उन नबी इस शब्द का मूल मौलिद है जिसका अर्थ अरबी में जन्म है। अरबी भाषा में मौलिद-उन-नबी का मतलब है हजरत मुहम्मद का जन्मदिन है। मौलिद के अलावा मवलीद या मौलूद भी कहा जाता है जिसका मतलब जन्मदिन है। नबी साहब के जन्मदिन पर सीरत और नात पढ़ी जाती है। इस्लाम में बेहद अहम यह दिन इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन मनाया जाता है। हालांकि मोहम्मद साहब का जन्मदिन एक खुशहाल अवसर है लेकिन मिलाद-उन-नबी को कई जगह शोक के दिन के रूप में भी मनाया जाता है। क्योंकि रबी-उल-अव्वल के 12वें दिन ही पैगंबर मोहम्मद साहब खुदा के पास वापस लौट गए थे। यह उत्सव मोहम्मद साहब के जीवन और उनकी शिक्षाओं की भी याद दिलाता है। 1588 में उस्मानिया साम्राज्य में इसे व्यापक तौर पर मनाया गया जिसमें हर खास ओ आम शामिल हुआ था और तब से लेकर अब तक साल दर साल नबी साहब के जन्मदिन का जश्न और ज्यादा भव्य होता जा रहा है। दुनिया भर के अलग-अलग देशों में मुस्लिम धर्मावलम्बी इस त्यौहार को जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। ईद मिलाद उन नबी को अलग-अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। अरबी में ईद अल-मौलीद अन-नबी तो उर्दू में ईद मिलाद-उन-नबी कहा जाता है। बांग्लादेश श्रीलंका, मालदीव और दक्षिण भारत की भाषाओं में ईद-ए-मिलादुन नबी, ईजिप्ट की अरबी भाषा एल मूलेद (एन-नबवी) या मूलेद एन-नबी, तुनीश की अरबी भाषा में एल-मूलेद, वोलोफ भाषा में गमोव, अरबी में मौलूद और यौम अन-नबी अरबी में ही मौलीद अन-नबी (ब.व. अल-मवालिद), मलय भाषा में मौलीदुर-रसूल, इंडोनेशियन भाषा में मौलीदुर-नबी, मलेशियन भाषा में मौलूद नबी, स्वाहिली और हौसा भाषाओं में मौलीदी, दारी भाषा या पर्शियन या उर्दू में मौलूद-ए-शरीफ यानि शुभ जन्म, अल्जीरियन भाषा में मौलीद एन-नबोई एशरीफ, तुर्की भाषा में मेवलदूत या मेवलीद-इ शरिफ, बोस्नियन में मेवलूद या मेवलीद, अल्बेनियन में मेवलैदी, पर्शियन में मिलाद-ए पयम्बर-ए अकरम, जावनीस भाषा में मूलूद, संस्कृत या दक्षिण भारती भाषाओं में नबी या महानबी जयंती और अजेरी भाषा में मोवलूद कहा जाता है।

-- मोहम्मद साहब का जीवन

मोहम्मद साहब का जन्म सन् 570 में सऊदी अरब में हुआ था। 576 में आपकी मां आमेना का इंतेकाल हो गया।

राहुल के बयान- नादां की राजनीति देश के लिए जंजाल....?

(लेखक- ओमप्रकाश मेहता/ ईएमएस)

भारत की राजनीति के मौजूदा स्तर को देखकर आज देश का हर दुद्धिजीवी जागरूक नागरिक हैरान और परेशान है, क्योंकि यहां पक्ष और विपक्ष दोनों ही स्तर के राजनेता देश की नहीं, अपनी राजनीति में व्यस्त है, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेता, जहां मोदी जी के शासन के दशक के जश्न के नशे में खोए है, जो प्रतिपक्ष के नेता विदेशों में जाकर भारत के 'निंदागान' में व्यस्त है, अब ऐसे में देश और उसके देशवासियों के बारे में चिंता करने वाला कोई नही है, सभी अपनी आत्म प्रशंसा व अपने सुनहरे राजनीतिक भविष्य के रंगीन सपनों में खोए है, जबकि आम देशवासी को अपनी और अपने परिवार की चिंता से ही फुर्सत नही है, अर्थात कुल मिलाकर देश में प्रजातंत्र मात्र एक मीठी औपचारिकता बनकर रह गया है और देश के रहनुमां अपनी मौज मस्ती में उसी प्रजातंत्र का मजाक उड़ा रहे है, आखिर यह स्थिति देश को कहां ले जाकर खड़ा करेगी, अजा न तो सत्तापक्ष अपने दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन कर रहा है और न ही प्रतिपक्ष, आज देश के जागरूक बुद्धिजीवियों के लिए यही सबसे बड़ा चिंता का विषय है।

अब दिनों-दिन देश के आम नागरिक के लिए जीवन यापन भी मुश्किल होता जा रहा है, देश आज दो वर्गों में स्पष्ट विभाजित नजर आता है, एक वर्ग वह जो सत्ता व प्रतिपक्ष की राजनीति से जुड़कर 'शोषक' बना हुआ है, तो दूसरा वर्ग वह जो ईश्वर पर आस्था रख जैसे तैसे अपना जीवन बसर कर रहा है। ....और जहां तक देश के आधुनिक भाग्यविधाताओं (राजनेताओं) का सवाल है, वे इन्हीं असहाय व लाचार वग्र के नाम पर अपनी राजनीतिक चालें चलकर मौज-मस्ती कर रहे है और उन्हें देश या देशवासियों की कोई चिंता नही है, आजादी की हीरक जयंती हम इसी माहौल में मनाने को मजबूर है।

यदि हम हमारे भाग्यविधाताओं (राजनेताओं) की मौजूदा भूमिकाओं की ही बात करें तो ताजा उदाहरण कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में विपक्ष नेता राहुल गांधी का ताजा अमेरिकी दौरा है, वहां उनके द्वारा दिए गए बयानों से तो ऐसा लगता है कि वे अमेरिका सिर्फ और सिर्फ भारत की बुराईयां ही करने गए है वैसे जहां तक राहुल जी का सवाल है, उनका हमेशा विवादों से ही नाता रहा है, उनके विवादित होने में मैं उनको दोषी इसलिए नही मानता क्योंकि उन्हें राजनीति की वह वास्तविक ट्रेनिंग नही मिल पाई जो मिलना चाहिए न उन्हें यह ट्रेनिंग उनकी दादी इंदिरा जी दे पाई और उनके पिता श्री राजीव गांधी, अब वे जो भी राजनीति कर रहे है, वे अपनी ही सूझबूझ से कर रहे है, जिसमें ऐसी गलतियां होना स्वाभाविक है, इसलिए इसके लिए राहुल जी को दोष देना मैं ठीक नही समझता, शायद उनके सत्ता सलाहकार भी अपने अस्तित्व के भविष्य की चिंता के कारण उन्हें सही सलाह नही दे पा रहे है।

भारत के राजनीतिक पंडितों का यह भी मानना है कि मोदी जी की राजनीतिक मजबूती का मुख्य स्त्रोत प्रतिपक्ष की कमजोरी ही है, आज जो देश में प्रतिपक्ष नजर आ रहा है, वह अपने मूल दायित्वों को इसलिए ठीक से नही निभा पा रहा है क्योंकि उसे अपने स्वयं के अस्तित्व की भी चिंता है और साथ ही अपने आप पर भरोसा भी नही है, इसी कारण मोदी जी के शासन का एक दशक सफलता पूर्वक पूरा हो गया और यही स्थिति रही हो गृहमंत्री अमित शाह की 2029 की भविष्यवाणी भी सच हो जाएगी पर फिर प्रतिपक्ष कहां होगा, यह कल्पना ही व्यर्थ है? इन्ही सब स्थितियों और कारणोंसे भारतीय राजनीति और उनकी संभावनाओं की स्थिति डांमाडोल बनी हुई है और इस अस्थिरता के चलते सत्ताधारी ''लूट सके सो लूट'' की मुद्रा में है तो प्रतिपक्ष उन्हें अदृष्य सहायता करने में व्यस्त है, अब ऐसे में देश और देशवासियों की चिंता करने वाला कौन? सब भगवान भरोसे.....?

इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग में तेजी

पिछले छह महीनों के दौरान भारत में इलेक्ट्रॉनिक सामानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ष के दौरान इलेक्ट्रॉनिक सामानों के निर्यात में सालाना आधार पर 16.91 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में पिछले वर्ष की समान अवधि के निर्यात की तुलना में इसमें 21.64 प्रतिशत की वृद्धि हुई। बिजली उत्पादन के क्षेत्र में इस क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं और इस दिशा में मजबूत फोकस राष्ट्रीय विज्ञान फाउंडेशन (जीवीसी) की मदद से इसकी वृद्धि को बढ़ा सकता है। भारत में अब ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की जरूरत है और इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। इस लिहाज से इस क्षेत्र में 2018 से 2022 के बीच रोजगार में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है। उम्मीद है कि समीक्षा में भी इस ओर ध्यान दिया गया होगा। हालांकि, दुनिया के 4.3 ट्रिलियन डॉलर के वैश्विक क्वांटम कॉइन बाजार में भारत की हिस्सेदारी करीब 2 फीसदी है। इस मुद्दे के केंद्र में चीन का खास बाजार है और इन दोनों समूहों का निशाना यह है कि इसके शेयर लगातार 30 के दशक में गिर रहे हैं। झिंजियांग और मालाबार जैसे उभरते बाजारों ने भी नैतिक रूप से इस क्षेत्र में अपनी स्थिति मजबूत की है और इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में उनका प्रभाव चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इस संदर्भ में निधि आयोग की नई रिपोर्ट 'इलेक्ट्रॉनिक्स: पावरिंग द इन्फ्लुएंसर्स इन जीईसी' में उल्लेख किया गया है कि 2017 से 2022 के बीच इलेक्ट्रिक प्रौद्योगिकियों का उत्पादन बढ़ेगा और इसमें 13 तकनीकी विशेषज्ञों की नियुक्ति की गई है। यह निकाय समग्र अवसरों की ओर इशारा करता है, लेकिन आगे के विकास और एकीकरण की चुनौतियों को लेकरचिंताएं भी हैं। वर्तमान में भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन का उपयोग बाजार में मोबाइल फोन, हेडफोन, रेफ्रिजरेटर और ऐसे अन्य उपकरणों के प्रचार के उद्देश्य से किया जा रहा है। विनिर्माण क्षेत्र इन उपकरणों के आयात पर निर्भर है और डिजाइन के सीमित आकार के कारण बढ़ती मांग के कारण उपकरणों की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है इसके अलावा करों और टैक्सों में भी वृद्धि हो रही है,

खेल - समाचार

अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच रद्द तैयारियों का मौका गंवा दिया: गैरी स्टीड

ग्रेटर नोएडा (ईएमएस)। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कोच गैरी स्टीड ने कहा कि अफगानिस्तान के साथ टेस्ट मैच बिना कोई गेंद फेंके रद्द होने से हमने एशियाई दौरे की तैयारियों के लिए एक बढ़िया मौका खो दिया है। इससे खिलाड़ी और पूरा कोचिंग स्टाफ में निराशा है। स्टीड ने कहा कि हमें अभी श्रीलंका के खिलाफ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (डब्ल्यूटीसी) के 2 मैच खेलने हैं, जिसकी तैयारियों के लिए यह अच्छा मैच होता। हमारे लिए सबसे निराशाजनक बात

सरकार ने प्याज निर्यात पर लगा प्रतिबंध हटाया, बढ़ सकते हैं भाव?

- प्रतिबंध हटने से निर्यात प्रोत्साहन और किसानों की आमदनी में मदद मिलेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। केंद्र सरकार ने देश से निर्यात को प्रोत्साहन और किसानों की आय में बढ़ोतरी के उद्देश्य से प्याज और बासमती चावल के न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) पर लगी सीमाओं को हटा दिया। प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य 550 डॉलर प्रति टन तय किया गया था लेकिन विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना जारी कर इसे तत्काल प्रभाव से हटा दिया। इसी तरह वाणिज्य विभाग ने बासमती चावल के निर्यात के लिए पंजीकरण-सह-आवंटन प्रमाण पत्र (आरसीएसी) जारी करने के लिए 950 डॉलर टन के मौजूदा न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) को हटाने का निर्णय लिया है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस कदम से निर्यात प्रोत्साहन और किसानों की आमदनी में मदद मिलेगी। एपीडा (कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण) से इस निर्णय को लागू करने के लिए तत्काल कदम उठाने का अनुरोध किया गया है। इस दौरान एपीडा बासमती निर्यात के लिए किसी भी अवास्वतिक मूल्य पर होने वाले निर्यात अनुबंध पर करीब से नजर रखेगा। सरकार ने पिछले साल अक्टूबर की शुरुआत में बासमती चावल के निर्यात के लिए न्यूनतम कीमत को 1,200 डॉलर प्रति टन से घटाकर 950 डॉलर प्रति टन कर दिया था। अधिक कीमतों के कारण निर्यात प्रभावित होने की चिंताओं के चलते ऐसा किया गया था। सरकार ने 27 अगस्त, 2023 को प्रीमियम बासमती चावल की आड़ में सफेद गैर-बासमती चावल के अवैध निर्यात पर लगाम लगाने के लिए 1,200 अमेरिकी डॉलर प्रति टन से कम कीमत पर बासमती चावल के निर्यात की अनुमति नहीं देने का फैसला किया था। भारत का बासमती चावल का कुल निर्यात 2022-23 में कीमत के लिहाज से 4.8 अरब डॉलर रहा, जबकि मात्रा के लिहाज से यह 45.6 लाख टन था। इस दौरान विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने प्याज निर्यात की न्यूनतम मूल्य सीमा हटाने वाली अधिसूचना में कहा ?कि प्याज के निर्यात पर न्यूनतम निर्यात मूल्य (एमईपी) की शर्त तत्काल प्रभाव से और अगले आदेश तक हटा दी गई है। इस प्रमुख ?किचन के खाद्य सामग्री की उच्च खुदरा कीमतों के बावजूद प्याज पर एमईपी को हटाने का निर्णय लिया गया है। उपभोक्ता मामलों के विभाग द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार को प्याज का अखिल भारतीय औसत मूल्य 50.83 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि मॉडल मूल्य 50 रुपये प्रति किलोग्राम है। प्याज का अधिकतम मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम है और न्यूनतम मूल्य 28 रुपये प्रति किलोग्राम है।

जीएसटी आंकडों के जरिए जल्द किया जाएगा जीडीपी का आकलन!

- तरीके और तकनीक पर निर्णय विशेषज्ञ समिति लेगी

नई दिल्ली (ईएमएस)। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की गणना में सुधार के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय लेखा के आधार वर्ष में बदलाव की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नए स्रोत के रूप में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के आंकड़े इस्तेमाल कर सकता है। यह जानकारी मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी। अब तक जीएसटी नेटवर्क गोपनीयता का हवाला देकर मंत्रालय के साथ यह डेटा साझा करने का इच्छुक नहीं था। अधिकारी ने कहा ?कि राष्ट्रीय लेखा के लिए आधार वर्ष बदलने के बाद नए डेटा स्रोत भी शामिल किए जाएंगे और मासिक जीएसटी डेटा भी उनमें से एक है। हम डेटा का उपयोग करने के पहले उसे गोपनीय बनाएंगे। हम फिलहाल नए डेटा स्रोत नहीं शामिल कर सकते क्योंकि इससे तुलना में दिक्कत आएगी। इसके तरीके और तकनीक का निर्णय विशेषज्ञ समिति करेगी। जून 2024 में मंत्रालय ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी यानी एसीएनएएस को लेकर 26 सदस्यीय विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया था। इसकी अध्यक्षता अर्थशास्त्री विश्वनाथ गोलदार को सौंपी गई और इसे फरवरी 2026 तक आधार संशोधन का काम पूरा करने को कहा गया है। जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर कहते हैं कि जीएसटी डेटा, कंपनियों की बैलेंस शीट के डेटा का स्थान ले सकता है। फिलहाल कंपनी मामलों के मंत्रालय से हासिल इस डेटा का उपयोग जीडीपी के आकलन के स्रोत के रूप में किया जाता है। उन्होंने कहा ?कि कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का जीडीपी में उपयोग किए जाने में कुछ दिक्कतें हैं। जीएसटी के जरिये लेनदेन के वॉल्यूम और आउटपुट डेटा के मूल्य का बेहतर अनुमान लगाया जा सकता है। 2011-12 की जीडीपी सिरीज में कंपनी मामलों के मंत्रालय के आंकड़ों का इस्तेमाल शुरू होने के बाद एमओएसपीआई को विशेषज्ञों की आलोचना का सामना करना पड़ा था क्योंकि सांख्यिकी विभाग उपयोग किए जाने वाले डेटा सेट को उजागर नहीं करता था।

पश्चिम बंगाल को मोदी सरकार से अलग करें ममता, आजादी की करें घोषणा

-बांग्लादेश में कट्टरपंथी नेता रहमानी ने भारत के खिलाफ फिर उगली आग

ढाका,(ईएमएस)। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां कट्टरपंथियों का बोलबाला चलने लगा है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार की ओर से हाल ही में एक कट्टरपंथी नेता को जेल से रिहा किया गया था। अब उसने भारत को तोड़ने की बात कही है। उसने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भारत को तोड़ने का आग्रह करते हुए राज्य को मोदी सरकार से आजाद करने को कहा है। जशीमुद्दीन रहमानी हाफी अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) का प्रमुख है, जो अल-कायदा से जुड़ा संगठन है। उसने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से आग्रह किया है कि वह बंगाल को मोदी सरकार से अलग करें और अपनी आजादी की घोषणा करें।

रहमानी ने भारत को तोड़ने और दिल्ली में इस्लामी झंडा लगाने की चेतावनी भी दी है। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार ने पिछले महीने रहमानी को जेल से रिहा किया था। धर्मनिरपेक्ष ब्लॉगर्स की हत्या के मामले में दोषी पाए जाने के बाद 2013 से वह जेल में बंद था। रिहा होने के बाद वह एक बार फिर भारत के खिलाफ उगलने लगा है। वह एक वीडियो में कथित तौर पर भारत के टुकड़े करने की बात कह रहा है। इसमें वह चिकेन नेक के जरिए पूर्वोत्तर के राज्यों को काटने की भी बात कर रहा है। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान से कश्मीर के लिए मदद मांग रहा है।

शेख हसीना की सरकार हमेशा से भारत के प्रति उदार रही है लेकिन छात्रों के भारी विरोध प्रदर्शन के बाद वहगिरगई।अबबांग्लादेश पर नेशन लिस्ट पार्टी का कब्जा है, जिसका झुका व पाकिस्तान की तरफ है। शेख हसीना के जाते ही बांग्लादेश में उनके नेताओं और अल्पसंख्यकों पर हमले हुए। इसी बीच रहमानी की रिहाई की गई है, जो पहलेभी अपने भड़काऊ बयानों के लिए जाना जाता है। रहमानी वीडियो में नेपाल, चीन और बांग्लादेश की सीमा के करीब मौजूद सिलीगुड़ी कॉरिडोर (चिकेन नेक) का भी जिक्र करता है, जो 20 किमी का संकीर्ण रास्ता है।

रिपोर्ट के मुताबिक कट्टरपंथी रहमानी ने बांग्लादेश के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई को लेकर चेतावनी दी। रहमानी ने कहा कि बांग्लादेश सिक्किम या भूटान की तरह नहीं है। यह 18 करोड़ लोगों का देश है। किसी भी उकसावे का परिणाम रणनीतिक प्रतिशोध होगा। इसके बाद उसने कहा कि वह चीन की मदद से चिकेन नेक काट कर पूर्वोत्तर राज्यों को शेष भारत से अलग कर देगा। वह कह रहा है कि अगर आप बांग्लादेश की ओर एक कदम बढ़ते हैं तो हम चीन से चिकेन नेक को बंद करने के लिए कहेंगे। हम पूर्वोत्तर के राज्यों को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने को कहेंगे।

सोने के भाव 49 दिन में 7.21 फीसदी बढ़े, चांदी भी हुई महंगी

नई ?दिल्ली (ईएमएस)। सोने की कीमत शुक्रवार को 73,044 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई, जिसमें एक दिन में 1,243 रुपए की बढ़ोतरी देखी गई। यह 10 मई के बाद से सोने की सबसे बड़ी एक दिन की बढ़त है और 53 दिनों में पहली बार 73 हजार का स्तर पार किया गया है। सोने की कीमतों में यह तेजी 23 जुलाई को सरकार द्वारा सोने पर आयात शुल्क 15 फीसदी से घटाकर 6 फीसदी करने के बाद आई गिरावट के ठीक ?विपरीत है, जब कीमतें 68,131 रुपए प्रति 10 ग्राम तक गिर गई थीं। तब से अब तक 49 दिन में सोने के दाम 7.21 फीसदी बढ़ गए हैं। चांदी की कीमतों में भी शुक्रवार को 2,912 रुपए प्रति किलो की वृद्धि देखी गई, जिससे यह 86,100 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गई। इस बढ़ोतरी के पीछे इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी में चांदी की बढ़ती मांग एक बड़ा कारण है। सैमसंग द्वारा विकसित नई ईवी बैटरी, जो 9 मिनट में चार्ज हो जाती है, में सिल्वर का इस्तेमाल किया जाता है। अगर इस तकनीक का अधिक उपयोग हुआ, तो चांदी की मांग में भारी इजाफा होगा। अनुमान के मुताबिक अगर 20 फीसदी ईवी में यह बैटरी उपयोग होती है, तो सालाना 16,000 टन चांदी की जरूरत होगी, जो कुल वैश्विक उत्पादन का 60 फीसदी है। एक अमेरिकी निवेश फर्म के अनुसार सोने की कीमतों में इस साल 20 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई है। शुक्रवार को अमेरिकी बाजार में सोना 2,584 डॉलर प्रति आउंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचा। 2025 की शुरुआत तक कीमतें 15 फीसदी बढ़कर 2,700 डॉलर प्रति आउंस पहुंच सकते हैं। यह बढ़ोतरी अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में संभावित कटौती और वैश्विक केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की स्टॉकिंग के कारण हो सकती है।

आखिरकार चीन के तेवर पड़े नरम भारत से रिश्ते सुधरने की बनी संभावना

नई दिल्ली(ईएमएस)। गलवान घाटी संघर्ष के बाद भारत और चीन के रिश्ते बेहद खराब हो गए थे। दोनों देशों में तनातनी चल रही थी। इसी बीच खबर आ रही है कि अब चीन के तेवर नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। और माना जा रहा है कि अब दोनों देशों के रिश्तों में सुधार होने की संभावना बनी है।

भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्ष सलाहकार अजीत डोभाल ने लगातार इसके लिए पहल की हैं। अब चीन की तरफ से भी जो बयान सामने आए रहे हैं उससे रिश्ते सुधरने के संकेत मिल रहे हैं। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि पूर्वी लद्दाख के चार क्षेत्रों में सेनाओं के बीच तनातनी कम हुई है। रूस में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री वांग ई के बीच गुरुवार को ब्रिक्स देशों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक से इतर हुई बैठक में दोनों देश द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती देने के लिए सहमत हैं।

डोभाल और वांग की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि दोनों देश मानते हैं कि शांति और विकास के लिए दोनों देशों के बीच संबंधों का मजबूत होना जरूरी है। मालूम हो, चीन का ये बयान तब आया है जब भारतीय विदेशमंत्री एस जयशंकर ने एक दिन पहले जिनेवा में कहाथा कि चीन से 75 फीसदी विवाद का हलहाचुका है।चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग से शुक्रवार को प्रेस वार्ता के दौरान पूछा गया कि क्या दोनों देश पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध के कारण चार साल से अधिक समय से द्विपक्षीय संबंधों पर जमी बर्फ को हटाने के करीब हैं? इसपर माओ ने कहा कि दोनों सेनाओं ने चार क्षेत्रों से वापसी की है और सीमा पर स्थिति स्थिर है। उन्होंने कहा कि चार जगहों पर सैनिक पीछे हटे हैं। प्रवक्ता ने कहा, ''हाल के वर्षों में, दोनों देशों की अग्रिम मोर्चे पर तैनात सेनाओं ने चीन-भारत सीमा के पश्चिमी क्षेत्र में चार बिंदुओ से पीछे हटने का काम पूरा कर लिया है, जिसमें गलवान घाटी भी शामिल है। चीन-भारत सीमा पर स्थिति आम तौर पर स्थिर और नियंत्रण में है। उनकी यह टिप्पणी विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा जिनेवा में दिए गए बयान के एक दिन बाद आई है। जयशंकर ने कहा था कि चीन के साथ सैनिकों की वापसी से जुड़ी समस्याओं का लगभग 75 प्रतिशत समाधान हो गया है, लेकिन बड़ा मुद्दा सीमा पर बढ़ता सैन्यीकरण है।

बता दें कि भारतीय और चीनी सेनाओं के बीच मई 2020 से गतिरोध जारी है और सीमा विवाद का पूर्ण समाधान अभी तक नहीं हो पाया है। हालांकि, दोनों पक्षों ने टकराव वाले कई बिंदुओं से अपने-अपने सैनिकों को वापस बुला लिया है। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई भीषण झड़प के बाद दोनों देशों के बीच संबंधों में गिरावट आई। यह दशकों के बाद दोनों पक्षों के बीच हुआ सबसे गंभीर सैन्य संघर्ष था। भारत का स्पष्ट रुख है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति नहीं होगी, चीन के साथ उसके संबंध सामान्य नहीं हो सकते। गतिरोध को दूर करने के लिए दोनों पक्षों के बीच अब तक कोर कमांडर स्तर की 21 दौर की वार्ता हो चुकी है।

चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच सीमा मसले को लेकर दर्ज किए गए सुधार पर भी चर्चा हुई है। मिंग से जब पूछा गया कि पूर्वी लद्दाख में दोनों देशों की सेनाओं के बीच तनातनी के बाद बीते चार वर्षों से द्विपक्षीय संबंध सुस्त पड़े हैं, क्या इसे नई गति मिल सकती है। सवाल के जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देशों की सेनाओं को सीमा पर चार क्षेत्रों में शांति बनाए रखने का अहसास हुआ है। सीमा पर अभी स्थिति स्थिर है। स्विट्जरलैंड में थिंकटैंक 'जिनेवा सेंटर फॉर सिक्योरिटी पॉलिसी' के साथ संवाद सत्र में जयशंकर ने कहा कि जून 2020 में गल्वान घाटी में हुए संघर्षों ने भारत-चीन संबंधों को समग्र तरीके से प्रभावित किया।

घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में दो प्रतिशत घटी

नई दिल्ली (ईएमएस)। घरेलू यात्री वाहनों की थोक बिक्री अगस्त में सालाना आधार पर करीब दो प्रतिशत घटी है। मांग में गिरावट के बीच डीलरों के पास भंडार को कम करने के लिए कंपनियों ने आपूर्ति घटा दी, इसकारण थोक बिक्री कम हुई। उद्योग संगठन सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के आंकड़ों के मुताबिक घरेलू बाजार में डीलरों के भेजी गई कुल यात्री वाहनों की खेप पिछले महीने सालाना आधार पर 1.8 प्रतिशत घटकर 3,52,921 इकाई रही। यह आंकड़ा अगस्त 2023 में 3,59,228 इकाई था। आंकड़ों के मुताबिक पिछले महीने दोपहिया वाहनों की थोक बिक्री नौ प्रतिशत बढ़कर 17,11,662 इकाई हो गई। यह आंकड़ा एक साल पहले इसी अवधि में 15,66,594 इकाई था। पिछले महीने स्कूटर की थोक बिक्री 10 प्रतिशत बढ़कर 6,06,250 इकाई हो गई, जो अगस्त 2023 में 5,49,290 इकाई थी।

कंपनियों से डीलरों को बाइक की आपूर्ति पिछले महीने आठ प्रतिशत बढ़कर 10,60,866 इकाई रही, जो अगस्त 2023 में 9,80,809 इकाई थी। पिछले महीने कुल तिपहिया वाहनों की बिक्री बढ़कर 69,962 इकाई हो गई, जो एक साल पहले 64,944 इकाई थी।

अफगानिस्तान में आईएस ने की गोलीबारी.....14 शिया मुस्लिमों की मौत

-तालिबान और यूएन ने की निंदा, ईरान ने की सख्त कार्रवाई की मांग

काबुल,(ईएमएस)। मध्य अफगानिस्तान के शिया बहुल क्षेत्र में बंदूकधारियों ने 14 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसे इस साल के सबसे खतरनाक हमलों में से एक माना जा रहा है। तालिबान ने इस हमले की पुष्टि की और बताया कि इस घटना में छह अन्य लोग घायल हुए हैं। इस्लामिक स्टेट ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। यह हमला गुरुवार को हुआ था जब शिया बहुल घोर और दाईकुंडी प्रांतों के बीच यात्रा कर रहे लोगों पर हमला किया गया।

आईएस ने कहा कि उन्होंने हमले के दौरान मशीन गन का इस्तेमाल किया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नासिर कनानी के हवाले से बताया कि इस हमले में अफगान शिया को निशाना बनाया गया है जो इराक में धार्मिक स्थलों की यात्रा से लौट रहे थे। ईरान ने इस अमानवीय हमले की निंदा करते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

तालिबान के मुख्य प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद ने हमले की कड़ी निंदा की और कहा कि तालिबान प्रशासन लोगों और उनकी संपत्तियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम अपराधियों की तलाश कर रहे हैं और उन्हें जल्द ही कटघरे में खड़ा किया जाएगा। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन ने भी इस हमले पर चिंताजताई । उन्होंने एक्स पर लिख कि इसहमले में शिया समुदाय के कई लोग मारे गए और घायल हुए हैं। हम पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं और जिम्मेदार लोगों को सजा दिलाने के लिए जांच की मांग करते हैं।

त्योहारी सीजन में बढ़ेंगे तेलों के भाव

नई दिल्ली (ईएमएस)। त्योहारी सीजन के दौरान अगले कुछ ?दिनों में लोगों को खाने के तेलों की कीमतों में तेजी का सामना करना पड़ सकता है। सरकार ने विभिन्न खाने के तेलों पर कस्टम डयूटी बढ़ा दी है, जिसका असर कीमतों पर दिख सकता है। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने क्रूड और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल समेत कुछ अन्य खाने के तेलों पर कस्टम डयूटी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के एक नोटिफिकेशन के हवाले से बताया गया है- क्रूड व रिफाइंड पॉम ऑयल, सोयाबीन तेल और सनफ्लावर सीड ऑयल पर बेसिक कस्टम डयूटी (बीसीडी) बढ़ा दी गई है। ये बदलाव 14 सितंबर से लागू हो गए हैं। क्रूड पॉम ऑयल, क्रूड सोयाबीन तेल और क्रूड सनफ्लावर सीड ऑयल पर बेसिक कस्टम डयूटी अब 20ज्ञ है, जो पहले शून्य थी। वहीं रिफाइंड सनफ्लावर सीड ऑयल, रिफाइंड पॉम ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन तेल पर बेसिक कस्टम डयूटी अब 32.5 फीसदी है, जो पहले 12.5 फीसदी थी। वहीं कस्टम डयूटी की वृद्धि के बाद प्रभावी शुल्क दर क्रूड तेलों के लिए 5.5 फीसदी से बढ़कर 27.5 फीसदी हो गई है और रिफाइंड तेलों के लिए 13.75 फीसदी से बढ़कर 35.75 फीसदी हो गई है।

जुलाई में ईएसआईसी से 22.53 लाख नए कर्मचारी जुड़े

नई दिल्ली (ईएमएस)। इस साल जुलाई में कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआईसी) ने 22.53 लाख नए ग्राहक जोड़े जो एक साल पहले की समान अवधि के मुकाबले 13.32 प्रतिशत अधिक हैं। श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी पेरोल आंकड़ों से पता चलता है कि जुलाई 2023 में 19.88 लाख नए ग्राहक ईएसआईसी से जुड़े थे। ईएसआईसी के अस्थायी पेरोल आंकड़ों के मुताबिक इस साल जुलाई में 22.53 लाख नए कर्मचारी जुड़े हैं। आधिकारिक बयान के मुताबिक समीक्षाधीन महीने में 56,476 नए प्रतिष्ठानों को ईएसआई योजना के सामाजिक सुरक्षा दायरे में लाया गया है। आंकड़ों से पता चलता है कि आलोच्य महीने में जुड़े कुल 22.53 लाख कर्मचारियों में से 10.84 लाख कर्मचारी 25 वर्ष तक के आयु वर्ग के थे। यह संख्या कुल पंजीकरण का लगभग 48 प्रतिशत है। पेरोल आंकड़े का विश्लेषण दर्शाता है कि जुलाई में महिला सदस्यों का शुद्ध पंजीकरण 4.65 लाख था जबकि 71 ट्रांसजेंडर कर्मचारियों ने भी ईएसआई योजना के तहत पंजीकरण कराया।

बीएलएस इंटरनेशनल सिटिजनशिप इन्वेस्ट का करेगी अधिग्रहण

नई दिल्ली (ईएमएस)। बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज लिमिटेड (बीएलएस) ने दुबई की कंपनी ने सिटिजनशिप इन्वेस्ट (सीआई) का 3.10 करोड़ डॉलर अर्थात 260 करोड़ रुपये में अधिग्रहण करने की योजना बनाई है। कंपनी ने कहा कि शत प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करने के लिए एक महत्वपूर्ण करार पर हस्ताक्षर किए गये हैं। सीआई दुबई स्थित एक एडवाइजरी कंपनी है, जो 15 से अधिक देशों में निवास और नागरिकता प्राप्त करने के लिए फास्ट-ट्रैक निवेश कार्यक्रमों में विशेषज्ञता रखती है। उसने कहा कि यह सौदा 3.1 करोड़ डॉलर में किया गया है, जिसे कंपनी के आंतरिक स्रोतों से वित्त पोषित किया जाएगा। यह सौदा आवश्यक अनुमोदन के बाद 31 अक्टूबर तक पूरा होने की उम्मीद है।

टीसीएस के 30,000 कर्मचारियों को आयकर विभाग से मिला नोटिस

नई दिल्ली (ईएमएस)। देश की प्रमुख आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) के लगभग 30 ,000 कर्मचारियों को आयकर ?विभाग ने नो?टिस जारी ?किया है, जिसमें 50 हजार से 1.45 लाख रुपए तक की टैक्स मांगा गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक टीसीएस ने अपने कर्मचारियों से फिल हाल टैक्स भुगतान न करने के लिए कहा है। कंपनी का कहना है कि जब तक आयकर विभाग से स्पष्ट जानकारी नहीं मिल जाती, तब तक कर्मचारियों को टैक्स डिमांड की राशि जमा नहीं करनी चाहिए। टीसीएस के एचआर विभाग द्वारा भेजे गए इंटरनल ईमेल के अनुसार ये नोटिस वित्त वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में की गई टीडीएस कटौती से संबंधित हैं। कंपनी ने कहा है कि वह पहले इस विवाद की पूरी जानकारी प्राप्त कर इसका समाधान करेगी।

यूक्रेन सभी शर्त मान ले तो रुस युद्ध खत्म कर बातचीत को तैयार

-रूस ने भारत, ब्राजील और चीन के साथ साझा की अपनी पेशकश

मास्को,(ईएमएस)। रुस-यूक्रेन युद्ध खत्म होने के संकेत मिलना शुरु हो गए हैं। रूस ने बातचीत की यह पेशकश अपने रणनीतिक साझेदारों भारत, ब्राजील और चीन के साथ साझा की है। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वह बातचीत के लिए तैयार है। रूस ने इसके लिए कुछ शर्तें रखी हैं। रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल न हो,यूक्रेन तटस्थ रहे और यूक्रेन अपने कुछ इलाकों को रूसी क्षेत्र मान ले।

रुस की शर्त है कि यूक्रेन भविष्य में तटस्थ, गुटनिरपेक्ष और परमाणु हथियारों से मुक्त देश रहे, यूक्रेन अपने यहां से सेना हटा ले, लुहान्स्क, दोनेत्स्क, खेरसॉन और ज़ापोरिज्जिया को रूसी क्षेत्र के रूप में मान्यता दे। क्रीमिया और सेवस्तोपोल की स्थिति को अंतरराष्ट्रीय संधियों में मान्यता दी जाए। रूस पर लगे सभी पश्चिमी प्रतिबंध हटाए जाएं। रूस का कहना है कि अगर यूक्रेन इन शर्तों को मान लेता है तो वह युद्ध रोक देगा और बातचीत शुरू कर देगा। रूस ने यह भी कहा है कि वह यूक्रेनी सैनिकों की सुरक्षित वापसी की गारंटी देगा। रूस की इस पेशकश पर भारत, ब्राजील और चीन की क्या प्रतिक्रिया है, यह अभी साफ नहीं है।

पाकिस्तान में जहर मिला दूध पीने से 13 लोगों की मौत

लाहौर,(ईएमएस)। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जहर मिला दूध पीने से एक ही परिवार के 13 लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि कुछ करीबी रिश्तेदारों ने आशंका जताई है कि पीड़ितों को जहर दिया गया होगा क्योंकि परिवार के मुखिया का कुछ अन्य लोगों के साथ ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है। घटना 19 अगस्त को खैरपुर के पास हैबत खान ब्रोही गांव की बताई जा रही है जिसकी जानकारी शुक्रवार को लगी।

मीडिया रिपोर्ट में पुलिस ने बताया कि सक्कूर स्थित रासायनिक प्रयोगशाला द्वारा की गई जांच से पता चला है कि जिस दिन परिवार के सदस्यों की मौत हुई, उस दिन उन्होंने जो दूध पिया था, उसमें जहरीला पदार्थ मिला था। रिपोर्ट में मृतकों के शरीर में जहरीले पदार्थ की मौजूदगी पाई गई है।

भारतीय टीम अगले पांच माह रहेगी वयस्त

मुम्बाई (ईएमएस)। भारतीय क्रिकेट टीम का काफी व्यस्त कार्यक्रम है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम को अब बांग्लादेश , न्यूजीलैंड , दक्षिण अफ्रीका,ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के खिलाफटेस्ट सीरीज खेलनी है। इस प्रकार अगले पांच महीने उसे लगातार खेलना है। इस दौरान अनुभवी के साथ ही युवा क्रिकेटर भी टीम की ओर से अहम भूमिका निभाना चाहेंगे।

कार्यक्रम इस प्रकार है :

19 से शुरु होगी बांग्लादेश से सीरीज

बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को 2 टेस्ट और 3 टी20 मुकाबले खेलने हैं। पहला टेस्ट 19 सितंबर तो दूसरा 27 सितंबर को शुरू होगा। इसके बाद तीन टी20 6, 9 और 12 तारीख को होंगे। टी20 मुकाबले शाम 7 बजे तो टेस्ट मुकाबले सुबह साढ़े 9 बजे शुरू होंगे।

16 अक्तूबर से न्यूजीलैंड से मुकाबला

भारतीयटीम को न्यूजीलैंड के खिलाफ तीन टेस्ट मुकाबले खेलने हैं। पहला टेस्ट 16 अक्तूबर को होगा जबकि दूसरा 24 से 28 अक्तूबर तक जबकि तीसरा 1 नवंबर से। इसके मैच सुबह साढ़े 9 शुरू होंगे।

8 नवंबर से दक्षिण अफ्रीका से खेलेगी

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम 4 टी20 मुकाबले खेलेगी। इसकी शुरूआत 8 नवंबर को होगी। मुकाबले रात साढ़े 8 बजे शुरू होंगे। वहीं टी20 मुकाबले 8, 10,13और15नवंबर को खेले जाएंगे।

22 नवंबर से ऑस्ट्रेलिया से होगी टक्कर

भारतीय टीम को इसके बाद ऑस्ट्रेलिया में बॉडर गावस्कर ट्रॉफी खेलनी है।इसमें5 टेस्ट मैच होंगे। पहला टेस्ट 22 नवंबर से शुरू होगा। दूसरा 6 दिसंबरसे, तीसरा 14 दिसंबर से, चौथा 26दिसंबर से तो 5वां 3 जनवरी से होगा। नये साल में 22 जनवरी से इंग्लैंड से खेलेगी

ऑस्ट्रेलिया के बाद भारतीय टीम का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम 5 टी20 और 3 टी20 खेलेगी। टी20 मुकाबले शाम 7 बजे तो वनडे मुकाबले दोपहर डेढ़ बजे शुरू होंगे। टी20 मुकाबले 22, 25, 28, 31 जनवरी और 2 फरवरी को होंगे जबकि एकदिवसीय मुकाबले 6, 9 और 12 फरवरी को होंगे।

ग्वालियर में भारत-बांग्लादेश मैच 6 को, दिव्यांगजनों के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये टिकट की आनलाइन बिक्री 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से

ग्वालियर (ईएमएस) भारत और बांग्लादेश के बीच ग्वालियर में टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच श्रीमंत माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में छह अक्टूबर को खेला जाएगा ॅ मैच के लिए टिकटों की बिक्री प्रारंभ होने जा रही है।

मेजबान मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन (एमपीसीए) के अनुसार स्टूडेंट कंसेशन टिकट की कीमत 929 रुपये है। इस श्रेणी के दर्शकों के लिए ईस्ट गैलरी में सीट आरक्षित रहेंगी। टिकट आनलाइन उपलब्ध होंगे। एक दर्शक एक ही टिकट खरीद सकेगा। टिकट की आनलाइन बिक्री 17 सितंबर को सुबह 11 बजे से प्रारंभ होकर 19 सितंबर को सुबह 11 बजे तक जारी रहेगी। हालांकि यदि इसके बीच निर्धारित कोटे के टिकट समाप्त हो जाते हैं तो यह बिक्री वहीं समाप्त हो जाएगी।

दिव्यांगजनों के लिए टिकट की कीमत 300 रुपये है। दिव्यांगजन के लिए बैठक व्यवस्था नार्थ-ईस्ट गैलरी में होगी। टिकट वेबसाइट ग्हेरी.ग्ह या मोबाइल एप्लिकेशन घ्हेरी.इन पर बुक किए जा सकते हैं। कीमतों में सभी टैक्स और कोरियर का खर्च भी शामिल है। ग्वालियर के नवनिर्मित स्टेडियम में यह पहला अंतरराष्ट्रीय मैच होगा। इसके पहले सभी मैच कैप्टन रूपसिंह स्टेडियम में होते थे।

आयुष्मान योजना में मुफ्त इलाज ही नहीं, बुजुर्गों को मिल रहीं खास सुविधाएं

- आयुष्मान भारत योजना में 70 साल के सीनियर सिटिजंस को शामिल

नई दिल्ली (ईएमएस)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में बुजुर्गों को मुफ्त इलाज की बड़ी सौगात दी। केंद्र ने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 साल या इससे अधिक के सीनियर सिटिजंस को इसमें शामिल किया है और अब इस आयुवर्ग के बुजुर्गों को परिवार से अलग 5 लाख रुपये तक का फ्री इलाज मिल सकेगा लेकिन सिर्फ मुफ्त इलाज ही नहीं देश में बुजुर्गों को अलग-अलग स्कीम्स के तहत अन्य कई तरह की बड़ी सुविधाएं भी मिल रही हैं, जिसमें पेंशन से लेकर निवेश पर ज्यादा ब्याज तक शामिल है। केंद्र सरकार की खास योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य स्कीम के तहत सरकार ने बड़ा बदलाव करते हुए इसमें 70 साल या उससे ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को हेल्थ इंश्योरेंस कवर देने का ऐलान किया है, चाहे वह किसी भी कैटेगरी से आते हों। पहले से ही इस स्कीम में कवर किए गए परिवारों से संबंधित 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को अपने लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपये तक का अतिरिक्त टॉप-अप कवर दिया जाएगा। इस फैसले से 4.5 करोड़ परिवारों के 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को फायदा होगा। इस स्कीम के तहत कई बड़ी बीमारियों को कवर किया जाता है, इसमें कैंसर, हार्ट डिसीज और किडनी से जुड़ी बीमारी के अलावा कोरोना, मोतियाबिंद तक शामिल हैं। लाभार्थी देशभर में 29,000 से ज्यादा लिस्टेड अस्

एयरपोर्ट को मात देने वाला गिफ्ट सिटी का मेट्रो स्टेशन यात्रियों को यह आधुनिक सुविधा मुहैया कराएगा

गांधीनगर,14 सितंबर

जीएमआरसी (गुजरात मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन) द्वारा गुजरात और भारत सरकार द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित मेट्रो रेल नेटवर्क के दूसरे चरण की शुरुआत अब गिनती की रह गई है। मेट्रो का यह दूसरा चरण अहमदाबाद और गांधीनगर को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 सितंबर को सेक्टर-1 से इसका उद्घाटन करेंगे।

मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो से उपहार नगरी बसी का सफर करेंगे। गिफ्ट सिटी का मेट्रो स्टेशन, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेट्रो का उद्घाटन करेंगे, को एयरपोर्ट से भी बेहतर डिजाइन किया गया है। मेट्रो रेलवे के दूसरे चरण के शुरू होने से अहमदाबाद और गांधीनगर के बीच कनेक्टिविटी मजबूत होगी और लोगों की यात्रा तेज, सुरक्षित और निष्पक्ष होगी।

लगातार बढ़ते ट्रैफिक और महंगे परिवहन के खिलाफ मेट्रो एक उचित और विश्वसनीय परिवहन विकल्प बनी रहेगी। उदाहरण के लिए, एपीएमसी (वासना) से गांधीनगर सेक्टर-1 तक 33.5 किमी की मेट्रो यात्रा केवल 65 मिनट में पूरी हो जाती है, जिसकी लागत केवल ?35 होगी। इसकी तुलना में, टैक्सी से यात्रा में लगभग 80 मिनट लगते हैं जिसकी लागत ? 415 से अधिक है। ऑटोरिक्शा का किराया मेट्रो और उससे आगे के समय के साथ लगभग ?375 है। समय और लागत की बचत से मेट्रो परिवहन दैनिक यात्रियों, छात्रों और गांधीनगर और गिफ्ट सिटी के आसपास के क्षेत्रों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए पसंदीदा विकल्प बन जाएगा। इस सेवा के शुरू होने से अहमदाबाद की व्यस्त सड़कों पर यातायात को कम करने में मदद मिलेगी, जो प्रदूषण को रोकने में महत्वपूर्ण होगी।

दिव्यांगों के लिए मेट्रो सुविधा का लाभ उठाने के लिए रैंप और व्हीलचेयर भी उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अलावा, नेशनल बिल्डिंग कोड के दिशानिर्देशों के अनुसार टेक्सटाइल फ्लोरिंग, कम ऊंचाई के टिकट काउंटर, ब्रेल कॉल बटन और लिफ्टों और टॉयलेट में हैंडिल भी प्रदान किए गए हैं। स्टेशन के समीप भुगतान और अवैतनिक क्षेत्रों को अलग किया गया है। यात्री अनपेड एरिया से टिकट खरीदते हैं और पेड एरिया में प्रवेश करते हैं, जहां से वे प्लेटफॉर्म पर जाकर ट्रेन में चढ़ सकते हैं। यात्रियों की सुरक्षा के लिए आपातकालीन टेलीफोन, सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (पीएएस), यात्री सूचना प्रदर्शन प्रणाली (पीआईडीएस) आदि सुविधाएं प्रदान की जाती हैं।

प्रत्येक मेट्रो स्टेशन 140 मीटर लंबा, 20.5 मीटर चौड़ा, 20-25 मीटर ऊंचा है और इसमें प्रवेश-निकास सहित 5,340 वर्ग मीटर का निर्मित क्षेत्र है। प्रत्येक स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क के दोनों ओर 2 प्रवेश निकास हैं, जहाँ 4 लिफ्ट और 4 एस्केलेटर उपलब्ध कराए गए हैं। निर्माण चरण के दौरान परियोजना के डिजाइन और कार्यान्वयन के लिए लगभग 5,000 प्रत्यक्ष और 10,000 अप्रत्यक्ष जनशक्ति को नियोजित किया गया था। इसके अतिरिक्त, संचालन चरण के दौरान लगभग 1500 कर्मचारियों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

गुजरात की समृद्ध ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ-साथ सामाजिक और पर्यावरणीय सुविधाओं को प्रदर्शित करने के लिए स्टेशनों पर कलाकृतियाँ चित्रित की गई हैं।

गुजराती लैरी लालाठ ने एक महीने में 1.78 लाख विदेशी यात्रियों का रिकॉर्ड बनाया...

अहमदाबाद, 14 सितंबर

देश ही नहीं दुनिया की सीमाओं पर हल चलाने की गुजरातियों की पहचान एक बार फिर सच साबित हुई है. गुजरात में एक महीने में 1.78 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री यातायात दर्ज किया गया। देश के राज्यों में सबसे अधिक अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की संख्या दर्ज करने वाले राज्यों में गुजरात सातवें स्थान पर है। प्राप्त विवरण के अनुसार, जुलाई माह में गुजरात के हवाई अड्डों पर कुल 13.45 लाख यात्रियों का पंजीकरण हुआ है. जिसमें 11.67 लाख घरेलू और 1.78 लाख अंतरराष्ट्रीय यात्री पंजीकृत हुए हैं. इसमें अकेले अहमदाबाद के सरदार वल्लभभाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 1.67 लाख अंतरराष्ट्रीय और 8.33 लाख घरेलू यात्री भी शामिल हैं।

इस आंकड़े को साल 2023 से तुलना करके देखा जाए तो जनवरी से जुलाई तक 10.37 लाख यात्री आए. सात महीने में यह संख्या बढ़कर 63.01 लाख हो गई है. जुलाई में अहमदाबाद हवाई अड्डे से 1,119 अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और 6,433 घरेलू उड़ानें थीं। इस एक महीने में 10 लाख से ज्यादा यात्रियों का रजिस्ट्रेशन हुआ है.

दीपावली त्योहारों पर सूरत जीएसआरटीसी अतिरिक्त 2200 बसें चलाएगा : परिवहन मंत्री हर्ष संघवी

सूरत (ईएमएस) गुजरात राज्य पथ परिवहन निगम (जीएसआरटीसी) का सूरत विभाग सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात, कच्छ, दाहोद के अलावा महाराष्ट्र के धुलिया, नंदुरबार इत्यादि के लिए आगामी दीपावली त्योहारों पर अतिरिक्त 2200 बसों का संचालन करेगा। दरअसल सूरत में कच्छ, दाहोद समेत सौराष्ट्र, उत्तर गुजरात और महाराष्ट्र के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं। जो रोजगार के लिए सूरत में रहते हैं। दिवाली के समय ये लोग अपने पैतृक गांव में परिवार के साथ छुट्टियों का आनंद लेने और त्योहार मनाने जाते हैं। दिवाली के दौरान प्राइवेट लग्जरी बसों का किराया भी दोगुना हो जाता है। इस कारण जीएसआरटीसी बसों में यात्रियों की भीड़ बढ़ जाती है। ऐसे में यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो इसके लिए सूरत जीएसआरटीसी ने दीपावली पर अतिरिक्त 2200 बसें चलाने का फैसला किया है। यह जानकारी राज्य के परिवहन मंत्री हर्ष संघवी ने दी। सूरत में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि दूरदराज समेत शहरी इलाकों में रहने वाले नागरिकों के लिए हर दिन 8,000 से अधिक बसों का 32 लाख किलोमीटर का संचालन कर 23 लाख से 27 लाख यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाता है। सूरत में सौराष्ट्र, उत्तरी गुजरात और अन्य शहरों के लोग अपने परिवारों के साथ रहते हैं। ये सभी लोग दिवाली में किसी भी तरह के महंगे टिकट के चक्कर में न फंसे इसके लिए सरकार की ओर से उचित व्यवस्था की जाती है। जब कोई सामाजिक समारोह होता है तो अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाती है। उन्होंने बताया कि 26 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक 2200 से अधिक बसों की व्यवस्था की गई है। सूरत के कापोद्रा और अडाजण बस डिपो से शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक बसों का संचालन किया जाएगा। मेरी माताओं-बहनों को उनके गांव जाने के लिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की गई है।

यात्रियों की भीड़ को देखते हुए अहमदाबाद और वडोदरा से अतिरिक्त बसों की भी योजना बनाई जा रही है। महाराष्ट्र से धुलिया, नंदुरबार जैसी जगहों के लिए यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी और इसका संचालन उधना बस डिपो से किया जाएगा। परिवहन मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि ग्रुप बुकिंग कराने वालों को सोसायटी के परिसर से गांव तक बस से ले जाया जाएगा। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त बसें भी लगाई जा सकती हैं। यात्रियों को निजी बसों के महंगे टिकट खरीदने से बचाने के लिए एसटी निगम ने पूरी तैयारी कर ली है। राज्य के सभी नागरिकों से अनुरोध है कि वे इसका सुविधा का लाभ उठाएं और अपने परिवार और बच्चों के साथ त्योहार मना सकें, इसके लिए जीएसआरटीसी द्वारा की गई है। सूरत के उधना, कामरेज, अडाजण सहित निगम के सभी बस स्टेशनों पर ग्रुप बुकिंग और ऑनलाइन बुकिंग की व्यवस्था की गई है। मांग के अनुरूप और बसें आवंटित करने की तैयारी है।

सोसायटियों में बसें भेजने की व्यवस्था की गई है। अगर लोग जल्दी बुकिंग करा लें तो हम 2200 की जगह 4400 अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराने को तैयार हैं। बसों में जगह सीमित है। इसलिए यात्री सीमित सामान के साथ यात्रा कर सहयोग करें। व्यवस्था के अनुरूप नियम बनाये गये हैं और सभी को सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है।

17 सितंबर से वलसाड जिले में होगा 10वां चरण सेवासेतु कार्यक्रम

वलसाड, दि. 14 सितम्बर

राज्य के प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने और लोगों के व्यक्तिपरक अभ्यावेदन के समाधान में तेजी लाने के लिए पूरे राज्य के साथ-साथ वलसाड जिले में भी अगली तारीख पर बैठक होगी. सेवासेतु कार्यक्रम का 10वां चरण 17 सितंबर से शुरू होने जा रहा है. जिसमें विभिन्न विभागों की लगभग 55 सेवाएं ग्रामीणों को प्रदान की जाएंगी।

वलसाड जिले के 6 तालुकाओं में से, सेवासेतु कार्यक्रम में धरमपुर तालुका के 36 गांवों, पिंडवल गांव के प्राथमिक विद्यालय, कपराडा तालुका के 46 गांवों के लिए सिलधा मुख्य प्राथमिक विद्यालय, वलसाड तालुका के 43 गांवों के लिए डूंगरी स्टेशन प्राथमिक विद्यालय, 9 गांवों के लिए कवल ग्राम पंचायत शामिल हैं। वापी तालुका, पारदी तालुका के 17 गांवों के लिए, मोतीवाड़ा गांव के कोली समाजनी वाडी में और उमरगाम तालुक के 15 गांवों के लिए धोडीपाड़ा गांव के सांस्कृतिक भवन में सेवासेतु कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा।

जिला कलेक्टर श्री नैमेश दवे ने जिले में होने वाले सेवा सेतु कार्यक्रमों की जानकारी देते हुए बताया कि प्रत्येक तालुक में 3 सेवा सेतु कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे. प्रत्येक तालुक के गांवों को प्रत्येक गांव को कवर करते हुए 3 समूहों में विभाजित किया गया है। डी.टी. 17 सितंबर को पहले क्लस्टर में शामिल गांवों को कवर कर लिया गया है। फिर बचे हुए गांवों को अन्य दो समूहों में शामिल कर लिया गया है.

साथ ही जिला कलक्टर श्री दवे ने बताया कि विभिन्न दस्तावेज प्राप्त करने के लिए जन सेवा केन्द्र में प्रक्रिया शुल्क 100 रूपये है। 20 रुपये दिए जाते हैं लेकिन सेवासेतु में यह शुल्क माफ कर दिया गया है। इसी तरह शहरी क्षेत्रों में भी सेवासेतु कार्यक्रम चलेगा. जो 18-19 सितम्बर को वलसाड शहर में, वापी में। दिनांक 20 सितम्बर, पारडी। दिनांक 21 सितम्बर, धर्मपुर। 1 अक्टूबर और उमरगाम डीटी में। यह 11 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा. पूरे जिले में अगली तारीख 17 से शुरू होंगे सेवा सेतु कार्यक्रम. इसलिए जिला कलेक्टर द्वारा वलसाड के निवासियों से इन सेवासेतु कार्यक्रमों का लाभ उठाने की अपील की गई है।

जिला कलक्टर श्री नैमेश दवे एवं जिला विकास अधिकारी श्री अतिराग चपलोत के मार्गदर्शन में नागरिकों को उनके निवास के निकटतम स्थान पर व्यक्तिगत सेवाएँ उपलब्ध कराने के महान उद्देश्य से शुरू किये गये इस सेवासेतु कार्यक्रम के दसवें चरण में उसी दिन. 17 सितंबर को होने वाले सेवासेतु कार्यक्रम में जिले के 6 तालुका के कुल 166 गांवों को शामिल किया जाएगा.

जिले के 6 तालुकाओं के संबंधित गांवों में आयोजित होने वाले इस सेवासेतु कार्यक्रम क्लस्टर में शामिल गांवों के लोगों को सेवासेतु स्थल से सरकार के विभिन्न विभागों की सेवाओं का लाभ मिलेगा। जिला प्रशासन ने इसका लाभ उठाने का अनुरोध किया है.

नाजायज संबंधों में श्रमिक की हत्या कर फरार आरोपी दंपत्ति महाराष्ट्र में ट्रेन से गिरफ्तार

वलसाड (ईएमएस) दक्षिण गुजरात के वलसाड में नाजायज संबंधों में एक युवक को अपनी जान गंवानी पड़ी। युवक की हत्या कर फरार आरोपी दंपत्ति को वलसाड पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से महाराष्ट्र के एक रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया और वलसाड ले आई और आगे की कार्यवाही शुरू की। जानकारी के मुताबिक वलसाड के अब्रामा रोड पर एक फैक्ट्री का काम चल रहा है, जहां 36 वर्षीय पप्पू पासवान नामक बिहार का मूल निवासी श्रमिक काम करता था। दो दिन पहले पप्पू के सिर पर हथौड़े और लोहे की रॉड से वार कर उसकी हत्या की घटना सामने आने के बाद वलसाड पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पता चला कि फैक्ट्री में काम करनेवाला विकास मांझी और उसकी पत्नी चंपा मांझी भी घटना के बाद से गायब हैं। इस खुलासे के बाद पुलिस ने सबसे पहले गायब मांझी दंपत्ति की तलाश शुरू कर दी। टेकनिकल जांच में पता चला कि मांझी दंपत्ति ट्रेन में अपने गांव बिहार जा रहा है। वलसाड पुलिस ने रेलवे पुलिस की मदद से महाराष्ट्र के जलगांव स्टेशन से विकास मांझी और चंपा मांझी को गिरफ्तार कर लिया और वलसाड लाकर दोनों से पूछताछ शुरू कर दी। पूछताछ में पता चला कि मृतक पप्पू पासवान और आरोपी विकास मांझी दोनों बिहार में पास के गांव में रहते थे। मृतक पप्पू पासवान कुछ दिन पहले अपने गांव गया था जहां वह आरोपी विकास मांझी और उसकी पत्नी चंपा देवी को काम दिलाने के बहाने वलसाड ले आया था। मृतक पप्पू पासवान और आरोपी चंपादेवी अपने गांव में एक साइकिल रेस के दौरान मिले थे और मोबाइल नंबरों का आदान-प्रदान करने के बाद अक्सर बातचीत हुई। जिसके बाद दोनों के बाच नाजायज संबंध कायम हो गए। अपनी प्रेमिका चंपा को साथ रखने के लिए उसे और उसके पति को काम के बहाने वलसाड बुलाया गया था। जहां पप्पू पासवान और विकास मांझी जलाराम इंडस्ट्रियल पार्क में बन रही इस नई फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आरोपी विकास मांझी अपनी पत्नी के साथ रह रहा था। पूछताछ में खुलासा हुआ कि घटना की रात मृतक पप्पू पासवान के साथ चंपा मांझी को विकास मांझी ने आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था। जिसके बाद विकास ने अपनी पत्नी चंपा को जगाया और उसके साथ मिलकर पप्पू पासवान के सिर पर हथौड़े और लोहे के पाइप से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया और वहां से भाग निकले। हालांकि आरोपी मांझी दंपत्ति के बिहार पहुंचने से पहले ही पुलिस ने दोनों को महाराष्ट्र में ट्रेन से ही उठा लिया और पप्पू पासवान की हत्या की गुत्थी सुलझा ली।

मुखबिर की हत्या के लिए नाबालिग लड़कों को दी सुपारी, मुख्य आरोपी समेत तीन गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस) शहर के दाणीलीमडा क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। जिसमें मुखबिर की हत्या के लिए एक शख्स ने दो नाबालिग लड़कों का उपयोग किया। नाबालिग लड़कों के हमले में मुखबिर घायल हो गया और उसने अपने हुए हमले की शिकायत दर्ज करवा दी। जिसके आधार पर पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत दोनों नाबालिग लड़कों को गिरफ्तार कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। जानकारी के मुताबिक अहमदाबाद के दाणीलीमडा क्षेत्र में रहनेवाला लड़क अंसारी नामक शख्स ड्रग्स, शराब समेत नशीले पदार्थों का काला कारोबार करता था। लड़क अंसारी को शक था कि उसके काले कारोबार की जानकारी शहर के इसनपुर क्षेत्र में रहनेवाला आमीन कुरैशी नामक व्यक्ति पुलिस को देता है। इसी शक के आधार पर लड़क ने आमीन की हत्या की योजना बनाई है और इसके लिए उसने दो नाबालिग लड़कों को सुपारी दे दी। साथ ही नंबर प्लेट बगैर की एक बाइक भी दी ताकि पकड़े जाने का खतरा ना हो। जिसके बाद लड़कों ने आमीन का पीछा किया और रास्ते में उसे रोक लाठी और पाइप से हमला कर दिया। इस घटना में घायल होने के बाद आमीन ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। पुलिस ने घटनास्थल समेत आसपास लगे सीसीटीवी खंगालने के बाद दो नाबालिग लड़कों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। दोनों लड़कों ने अपने माता-पिता की उपस्थिति में आमीन पर हमला करने की बात कबूल कर ली और बताया कि इसके लिए लड़क अंसारी ने उन्हें सुपारी दी थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने लड़क अंसारी को भी गिरफ्तार कर लिया। आमीन की हत्या के लिए लड़क ने लड़कों को चार हजार रुपए एडवांस दिए थे और बाकी रुपए काम होने के बाद देने का वादा किया था। पुलिस पूछताछ में लड़क ने बताया कि उसी ने नाबालिग लड़कों को आमीन की तस्वीर मोबाइल में दिखाई थी और उसके आने-जाने के रास्ते समेत अन्य दैनिक गतिविधियों की जानकारी दी थी। लड़क अंसारी ने नाबालिग लड़कों का इस्तेमाल किया क्योंकि अगर पुलिस में मामला दर्ज हुआ और वे पकड़े गए तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा और सजा भी होगी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि लड़क अंसारी के खिलाफ 11 जितने आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आमीन पर हमले में उपयोग किए गए हथियार के अलावा लड़क के घर से चार लाख रुपए नकद और मोबाइल इत्यादि जब्त कर आगे की कार्यवाही शुरू की है।

बैग चोरी की जांच:बनाने के आरोप में शहबाज गिरफ्तार

अहमदाबाद,14 सितंबर

कुछ दिन पहले कालूपुर रेलवे स्टेशन पर हर्षित चौधरी नाम के एक आर्मी युवक को गिरफ्तार किया गया था और उसने फर्जी नाम बताकर और मुस्लिम के रूप में अपनी पहचान छिपाकर कई लोगों को धोखा देने की बात कबूल की है। आरोपी से पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि वह शादी डॉट कॉम पर हर्षित चौधरी बनकर हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाता था और उनके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और पैसे ऐंठता था। पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है.

पुलिस ने जब बैग चोरी के संदेह में हर्षित चौधरी नाम के युवक को कालूपुर रेलवे स्टेशन से उठाया तो उसके पास से हर्षित चौधरी का सेना का पहचान पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड तथा मोहम्मद खान नाम के व्यक्ति का आधार कार्ड मिला. इस पर संदेह होने पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि हर्षित चौधरी का असली नाम मोहम्मद शहबाज मुस्तअली खान (निवासी मौलाना आजादनगर, शाही मस्जिद के बगल, अलीगढ़, यूपी) है। पुलिस ने उसके पास से मिले फर्जी दस्तावेज के आधार पर उसे रिमांड पर लिया। फिर उसे अपने साथ अलीगढ़ ले गए।

वहां पुलिस को पता चला कि मोहम्मद शहबाज हर्षित चौधरी का नाम बताकर शादी डॉट कॉम पर नियमित रूप से लड़कियों से शादी के लिए मिलता था और उनसे शादी करने की बात करता था. बाद में वह लड़की से मिलता था और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता था और उससे पैसे भी वसूलता था। यूपी के अलीगढ़ में भी एक लड़की ने मोहम्मद शहबाज के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.

मिली जानकारी के मुताबिक, शहबाज ने जम्मू कश्मीर, सिलीगुड़ी, गुजरात, मुंबई, दिल्ली, अलीगढ़ समेत देश के अलग-अलग जगहों पर 14 हिंदू लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाया और शारीरिक संबंध बनाकर लड़कियों से 50 लाख से ज्यादा की रकम वसूल की. चौंकाने वाली बात यह है कि आरोपी काफी समय पहले सेना में कार्यरत था और उसे मेडिकल आधार पर बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन आज तक आरोपी लड़कियों को खुद को मेजर बताता था।

आरोपी ने 2016 में अलीगढ़ में एक मुस्लिम लड़की से शादी भी की है और इस रिश्ते से उसके दो बच्चे भी हैं। आरोपी का भाई एयरफोर्स में ऑफिसर है जबकि पिता रिटायर आर्मी ऑफिसर हैं. इसके अलावा पुलिस को हर्षित चौधरी के नाम से पंजाब नेशनल बैंक का एक खाता भी मिला. ट

पीएम के गुजरात आने से पहले सरकार ने कर्मचारियों का आंदोलन किया स्थगित, सौहार्दपूर्ण समाधान का दिया आश्वासन

गांधीनगर,14 सितंबर

गुजरात सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना विरोध: 17 सितंबर को गुजरात राज्य के विभिन्न कर्मचारी संगठनों को सरकार के खिलाफ विभिन्न मुद्दों पर कलम बंद रखना था। लेकिन उससे पहले सरकार ने कर्मचारियों के साथ बैठक कर एक हफ्ते का समय मांगा है. चूंकि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे पर हैं, इसलिए गुजरात सरकार की बेइज्जती से बचने के लिए आंदोलन स्थगित कर दिया गया है। हालांकि, सरकार के मंत्री ने आरोप लगाया है कि पीएम के गुजरात दौरे के कारण अधिकारी और मंत्री व्यस्त हैं.

प्रदेश मंत्री जगदीश विश्वकर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि गुजरात स्टेट काउंसिल की ओर से एक टीम का गठन किया गया है. इसने इस विषय को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा है, जिस पर वे अब तक सकारात्मक रुख अपनाते रहे हैं। हमने पिछली सरकार में उनके सवाल सुने थे और अगले सप्ताह फिर बैठक होगी और कर्मचारियों की मांगों के संबंध में सौहार्दपूर्ण समाधान पर चर्चा की जाएगी।

कार्मिक बोर्ड के भरत चौधरी और सतीशभाई ने सरकार की बात स्वीकार कर ली है. लेकिन अक्टूबर में उनकी मांग का सुखद अंत नहीं होने पर चिमकी ने आक्रामक कार्यक्रम आयोजित करने की धमकी दी है.

इस मुद्दे पर कर्मचारी एवं प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रतिनिधि दिग्विजय सिंह जाडेजा ने कहा कि इससे पहले 16 सितंबर 2022 को पुरानी सरकार में 14 प्रश्न स्वीकृत किए गए थे और 2 प्रश्न स्वीकृत नहीं किए गए थे. इस बार हमने नए प्रश्नों में 7 प्रश्न और शामिल किए हैं, जिनमें से 2-3 प्रश्नों पर सरकार के साथ चर्चा करना आवश्यक है। सरकार ने हमसे एक हफ्ते का समय मांगा. हम सरकार के साथ बैठकर समाधान निकालना चाहते हैं और निकट भविष्य में त्वरित कार्रवाई करना चाहते हैं।

इससे पहले, सरकारी कर्मचारियों ने पुरानी पेंशन योजना सहित अपनी लंबित मांगों को लेकर गांधीनगर में आंदोलन किया था। 23 फरवरी को सरकारी कर्मचारियों ने गांधीनगर के सत्याग्रह शिविर में प्रदर्शन किया. उपस्थिति की घोषणा संयुक्त कर्मचारी महासंघ ने की। इससे पहले 14 और 16 फरवरी को शिक्षक-शिक्षिकाओं ने बांह पर काली पट्टी बांधकर ड्यूटी की थी. कर्मचारियों की पुरानी पेंशन समेत सातवें वेतन आयोग के लंबित लाभ के भुगतान के साथ-साथ महंगाई भत्ता और मकान किराया भत्ता भी केंद्रीय आधार पर देने की मांग की जा रही है. बता दें कि संगठन ने सरकार को 4 मार्च तक समस्याओं का समाधान करने का अल्टीमेटम दिया था.

पुरानी पेंशन योजना के तहत सेवानिवृत्त कर्मचारी पेंशन के हकदार थे। जिसमें रिटायरमेंट के समय नौकरी की सैलरी का 50 फीसदी हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा. इसमें कर्मचारी मूल वेतनमान पर जितना काम पूरा करता है, रिटायरमेंट के समय उसका आधा हिस्सा पेंशन के रूप में दिया जाता है।

पुरानी पेंशन योजना में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को कामकाजी कर्मचारी की तरह महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते मिलते रहते हैं, यानी अगर सरकार कोई भत्ता बढ़ाती है तो पेंशन भी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी।

अपनी मांग को लेकर मोबाइल टावर पर चढ़ा किसान;

राजपीपला: नर्मदा जिले में एक किसान अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गया. नर्मदा जिले के गरुड़ेश्वर तालुका का एक प्रभावित किसान अपनी मांग को लेकर आत्महत्या करने के इरादे से टावर पर चढ़ गया और कहा कि 'जहां सुधि चैतर वसावा मुझे न्याय नहीं देंगे तो सुधि नीचे नहीं उतरेंगे.'

नर्मदा जिले के किसान गणपत तड़वी आज सुबह-सुबह मोबाइल टावर पर चढ़ गये. घटना की सूचना मिलते ही नांदोद विधायक डॉ. दर्शनाबेन देशमुख घटनास्थल पर पहुंचीं। और उन्होंने किसान की बात सुनी और समस्या के सटीक समाधान का आश्वासन दिया.

किसानों की मांग है कि हमारे बुजुर्गों की जमीन छीन ली गई है और कोई मुआवजा या लाभ नहीं दिया गया है. स्थानीय प्रशासन की भर्ती प्रक्रिया में भी नियुक्ति नहीं दी जाती है. उन्होंने यह भी कहा कि अगर कोई मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने आत्महत्या करने की धमकी दी.

भादौ पूर्णिमा मेला के शुरुआती तीन दिनों में 9.88 लाख श्रद्धालुओं ने किये अम्बाजी के दर्शन

बनासकांठा (ईएमएस) 51 शक्तिपीठों में से एक उत्तर गुजरात स्थित अम्बाजी शक्तिपीठ में एक सप्ताह तक चलने वाले भादौ पूर्णिमा महामेला का 12 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। भादौ पूर्णिमा के मेला में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। अम्बाजी कीओर जानेवाले हर रास्ते और गलियां श्रद्धालुओं से अटी पड़ी हैं। हजारों की संख्या में पदयात्रियों के के समूह अम्बाजी की ओर बढ़ रहे हैं। जानकारी है कि मेला के प्रारंभ होने के शुरुआती तीन दिनों के भीतर 9.88 लाख जितने श्रद्धालुओं ने अम्बाजीके दर्शन किये। जिसमें आज यानी शनिवार को 4.49 लाख से ज्यादा श्रद्धालओं ने अम्बाजी के दर्शन कर धन्यता महसूस की। मंदिर के भंडारे में करीब 1.77 लाख जितने श्रद्धालुओं ने प्रसाद लिया। आज 7.55 लाख से ज्यादा मोहनथाल प्रसाद के पैकेट का वितरण किया गया। अम्बाजी आनेवाले प्रत्येक श्रद्धालु में जबर्दस्त उत्साह नजर आ रहा है। अम्बाजी शक्तिपीठ में एक सप्ताह तक चलने वाले भादौ पूर्णिमा महामेला का 12 सितंबर से प्रारंभ हो गया है। भादौ पूर्णिमा के मेला में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। अम्बाजी कीओर जानेवाले हर रास्ते और गलियां श्रद्धालुओं से अटी पड़ी हैं।

एनसीईआरटी कक्षा 6 की नकली किताब बेचने का घोटाला पकड़ा गया

गांधीब्रिज के पास एक स्टेशनरी दुकान में छापेमारी

अहमदाबाद,14 सितंबर

शहर के कालूपुर ब्रिज के पास एक पुस्तक विक्रेता द्वारा एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें बेचे जाने की सूचना के आधार पर कालूपुर पुलिस ने छापेमारी की और कक्षा 6 की किताबें जब्त कर कानूनी कार्रवाई की. इस मामले की जांच में एनसीईआरटी की नकली किताबें बेचने के बड़े घोटाले का खुलासा होने की संभावना के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. चांदखेड़ा इलाके में रहने वाले कपिल पाल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसोर्सेज में काम करते हैं और अहमदाबाद में प्रशिक्षण।

उन्हें एनसीईआरटी प्रमुख अनुपकुमार राजपूत ने सूचना दी कि अहमदाबाद में गांधी ब्रिज के पास एक दुकान में एनसीईआरटी की डुप्लीकेट किताबें असली बताकर बेची जा रही हैं। जिसके आधार पर कालूपुर पुलिस ने गांधी ब्रिज के नीचे न्यू झवेरी बुक सेंटर पर छापा मारा और एनसीईआरटी कक्षा 6 की मल्हार नामक पाठय पुस्तक की 13 प्रतियां पाईं, जिसे गुंजन जावेरी असली किताब के रूप में बेच रहा था। इस संबंध में पुलिस ने कॉपीराइट एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया और यह किताब कहां से खरीदी गई? मुद्रण किसने किया? सूत्रों के मुताबिक, एनसीईआरटी की असली किताबों की बिक्री में कारोबारी 20 फीसदी मार्जिन के साथ 65 रुपये में किताब बेच रहे हैं, इस दिशा में जांच का पहिया तेज कर दिया गया है। लेकिन, डुप्लीकेट बुक में व्यापारी को 50 फीसदी का मार्जिन मिलता था. इसलिए मुनाफ़ा बढ़ाने के लिए नकली किताबें बेची गईं।

पीएम मोदी आज से दो दिवसीय गुजरात दौरे, अहमदाबाद-गांधीनगर मेट्रो ट्रेन का करेंगे उदघाटन

अहमदाबाद (ईएमएस) प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से गुजरात दौरे पर आ रहे हैं। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी गुजरात को कई सौगातें भी देने वाले हैं। पीएम मोदी 16 सितंबर को मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। मेट्रो फेज-2 मोढेरा से गांधीनगर सेक्टर-1 तक जुड़ेगा। इतना ही नहीं बल्कि मेट्रो फेज-2 का एक कॉरिडोर गिफ्ट सिटी, गांधीनगर और अहमदाबाद को जोड़ेगा। प्रधानमंत्री इसी मेट्रो के दूसरे चरण का उद्घाटन करेंगे। आने वाले समय में मेट्रो सचिवालय, अक्षरधाम, पुराना सचिवालय, सेक्टर 16, सेक्टर 24 और महात्मा मंदिर तक जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी 20.8 किमी लंबे कॉरिडोर और फेज 2 के 8 स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। मोटेरा से सेक्टर 1 तक 15.4 किमी और इसमें 6 स्टेशन और 5.4 किमी 2 स्टेशन लिंक लाइनें शामिल हैं। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना चरण-2 मोटेरा और गांधीनगर के बीच जुड़ा हुआ है। चरण 2 अहमदाबाद मेट्रो चरण-1 के उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरिडोर की निरंतरता है। मुख्य लाइन एपीएमसी से मोटेरा लाइन का विस्तार है और महात्मा मंदिर तक जाती है। शाखा लाइन जीएनएलयू से शुरू होती है और गिफ्ट सिटी पर समाप्त होती है। गौरतलब है कि मेट्रो फेज 2 रेल लाइन की कुल लंबाई 28.2 किमी है। इसमें 22.8 किमी मुख्य लाइन और 5.4 किमी शाखा लाइन शामिल है। मुख्य लाइन में 20 स्टेशन हैं और शाखा लाइन में 2 स्टेशन हैं। मेट्रो फेज-2 प्रोजेक्ट की कुल लागत 5,384 करोड़ रुपये हैं।

पीएम मोदी के दौरे के दौरान अहमदाबाद में इन चीजों के इस्तेमाल पर रहेगी रोक

अहमदाबाद,14 सितंबर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे के दौरान ड्रोन पर प्रतिबंध: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 से 17 सितंबर तक गुजरात के दौरे पर हैं। जिसके चलते पुलिस ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की कवायद तेज कर दी है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने एक अधिसूचना जारी की है. जिसमें शहर के सभी इलाकों में 'नो ड्रोन फ्लाई' की घोषणा की गई है.

इन डिवाइस पर लगे बैन - रिमोट नियंत्रित ड्रोन - क्वाड कॉप्टर- चालित विमान - गर्म हवा का गुब्बारा

प्रधानमंत्री ने मोटेरा और गांधीनगर के बीच मेट्रो ट्रेन चल